राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 01 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-271 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

95 साल बाद जनगणना में पूछी जाएगी आपकी जाति

यूपी और पंजाब समेत 5 चुनावी राज्यों में फिलहाल नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में जनगणना का दूसरा फेज 25 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जो 28 फरवरी तक चलेगा। इस बार 40 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों की गिनती का पहला फेज जून 2026 में पूरा हो चुका है। बड़ी बात ये कि 95 साल बाद यानी 1931 के बाद पहली बार देश में जाति की गिनती हो रही है। 5 राज्यों मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में जनगणना होगी। इन राज्यों में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बर्फबारी वाले क्षेत्रों- लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और

हिमाचल प्रदेश में भी जनगणना नहीं होगी। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 10 से 24 जनवरी 2027 तक आप खुद पोर्टल पर डेटा भर सकते हैं।

इन राज्यों में जनवरी-फरवरी में जनगणना नहीं

मणिपुर में जातीय हिंसा की वजह से हालात अभी सामान्य नहीं है। इसलिए मणिपुर की जनगणना अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए स्टाफ चुनाव में लगेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बर्फ वाले इलाके जैसे लाहौल-स्पीति, किन्नौर के ऊंचे इलाके। यहां बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो जाते हैं। यहां सितंबर-अक्टूबर में हो सकती है। गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सेंसस एक्ट 1948 की धारा 3 के तहत आदेश जारी हुआ है।

आशुतोष दीक्षित ने संभाला 'वायु सेना प्रमुख' का कार्यभार

तीन प्रमुख सैन्य ऑपरेशनों में दिखा चुके हैं अपनी ताकत

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 31 अक्टूबर 2026 को 29वें वायु सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का स्थान लिया है, जो देश की 42 वर्षों की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। आशुतोष दीक्षित का पिछले 40 वर्षों में दमदार करियर रहा है। तीन प्रमुख सैन्य अभियानों में दमदार भूमिका निभाने के साथ आशुतोष दीक्षित को अलग-अलग तरह के विमानों को उड़ाने का 3300 घंटे से अधिक का अनुभव है। वह वायु सेना के अधिकारियों के बीच समन्वय बनाने के लिए जाने जाते हैं।

तीन प्रमुख सैन्य अभियानों में निभा चुके अपनी भूमिका

कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर में अहम भूमिका निभा चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन रक्षक में अहम भूमिका निभा चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी।

हरियाणा और आंध्र में दिल दहलाने वाली वारदात

पंचकूला में केजी की बच्ची के सिर पर 12 बार ईंट मारी

पंचकूला (एजेंसी)। हरियाणा के पंचकूला के एक प्रसिद्ध स्कूल में केजी की छात्रा पर तीसरी कक्षा के छात्र ने बेरहमी से हमला कर दिया। छात्र ने बच्ची का सिर पहले बेंच पर मारा, फिर 19 बार पैर से उसके चेहरे पर लात-घूसों से वार किया। उसके बाल पकड़कर घसीटा। बाद में ईंट से 12 बार बच्ची के सिर पर हमला किया। 96 सेकेंड तक लगातार बच्ची को बेरहमी से पीटे जाने की घटना क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज देखकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी कहा इसे पूरा देखना भी मुश्किल है। उन्होंने मामले की जांच के लिए कमेटी

गठित करने को कहा है। घटना की जानकारी उस वक्त सामने आई जब ऑटो ड्राइवर बच्ची को लेने स्कूल पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की।

आंध्र में 10वीं की छात्राओं पर काटने वाली आरी से हमला

अनंतपुर (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में शनिवार को स्कूल की क्लास के अंदर 10वीं की छात्रा पर पावर चेनसॉ (बिजली से चलने वाली आरी) से हमला किया गया। यह वारदात सुबह 10 बजे की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में छात्रा का दायां हाथ कट गया और चेहरे, गर्दन और कान पर गंभीर चोटें आईं। उसे बचाने पहुंची दूसरी छात्रा भी घायल हो गई। एक छात्रा की हालत सीरियस है।

संक्षिप्त समाचार

पटना स्नातक चुनाव में दिखा निशांत कुमार का दम!

जेडीयू में उभरा नया नेतृत्व, पार्टी के लिए साबित हुए 'ट्रम्प कार्ड'

पटना (एजेंसी)। बिहार में आठ सीटों के लिए संपन्न एमएलसी चुनाव के परिणाम चाहे जिसके पक्ष में आए हों, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के पुत्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस चुनाव के दौरान जिस लिटमस टेस्ट में शामिल हुए, उसमें उन्हें कमोबेश सफलता तो

मिल गई। खास कर पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को जिस तरह से जदयू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना डाला वो एक चुनौती तो थी। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पर जब जनता दल यू की गुटबाजी की छाया पड़ गई तो प्रथम दृष्टि में लगा कि ये सीट कहीं गुटबाजी की भेंट न चढ़ जाए। ठीक ऐसे समय में निशांत कुमार ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेवारी ली। पिता नीतिश कुमार का आशीर्वाद लिया और पहली चुनावी यात्रा नालंदा, नवादा से शुरू की थी। साथ में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को लेकर जन संपर्क स्थापित किया।

यूपी में भाजपा ने क्या किया, ये घर-घर पहुंचकर बताएंगे

विनोद तावड़े बोले-हैट्रिक जरूरी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हुआ रोडमैप

लखनऊ (एजेंसी)। भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले घर-घर पहुंचेगी। 2017 के बाद यूपी कैसे बदल गई। अपराध कैसे कम हुए, डेवलपमेंट कितना हुआ, ये लोगों को बताया जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्र में हुए कामों के वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे। ये फैसला प्रदेश पदाधिकारियों के

साथ प्रांतीय कार्यालय में हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा- गृहमंत्री अमित शाह ने जो रास्ता दिखाया है, सभी कार्यकर्ताओं को उस दिशा में पूरी शिद्दत से काम करना है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा- लखनऊ में आयोजित कार्यसमिति की बैठक में देश के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिला। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव बन चुकी है।

राहुल गांधी के दौरे से पहले 'पंजाब' के चुनाव पर मंथन

दिल्ली में कांग्रेस की हाई-लेवल मीटिंग, दिग्गज नेता जुटे!

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता के गलियारों में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पंजाब में सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं सूबे के सीएम भगवंत मान जोरदार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे से पहले हाई लेवल मीटिंग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीटिंग की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि पंजाब एक निर्णायक बदलाव और एक नई, परिवर्तनकारी शुरुआत के लिए तरस रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे लिखा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों के भरोसे को तोड़ा है।

पंजाब की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी कांग्रेस

उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के मान-सम्मान और गौरव को बहाल करने, इसके भविष्य को सुरक्षित करने, और राज्य में शांति, समृद्धि व प्रगति का एक नया दौर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बैठक में कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा समेत प्रदेश इकाई के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

इजराइल के आम चुनाव की होगी जांच

खुफिया एजेंसी मोसाद को मिला जांच का जिम्मा

तेल अवीव (एजेंसी)। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हफ्ते हुए चुनाव में विदेशी दखल के आरोपों की जांच करेगी। न्यूज चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस जांच में

विदेशी दखल का है आरोप नतीजों पर असर नहीं

आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट भी शामिल होगी। आरोप है कि कतर और कुछ दूसरे देशों ने मंगलवार को हुए चुनाव में अरब वोटर्स को पैसे देकर ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने की कोशिश की। इस चुनाव में अरब पार्टियों को कुल 19 सीटें मिली हैं। यह इतिहास में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी के नेताओं ने भी अरब पार्टियों पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इजराइल के केंद्रीय चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जांच का दायरा सीमित है। आयोग के मुताबिक, इस मामले से चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा है और न ही नतीजों पर सवाल उठता है। इजराइल में नेतन्याहू विरोधी दल सरकार बनाने का रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत जनता अलग से प्रधानमंत्री चुनेगी और इससे अरब पार्टियों के समर्थन के बिना अल्पमत सरकार बनाने का रास्ता खुल सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, हिब्रू मीडिया ने बताया कि विपक्षी गठबंधन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कानून लाने पर विचार कर रहा है।

जम्मू-कश्मीर में उमर के खिलाफ 24 विधायक लामबंद

4 दिन पहले बने चार मंत्रियों, सीएम के सलाहकार को हटाने की मांग

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद असंतोष के संकेत मिले हैं। पार्टी के 24 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। 18 विधायकों ने शुक्रवार को श्रीनगर में लोलाब विधायक कैसर जमशेद लोन के घर बैठक की, जबकि 6 विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। विधायकों ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी और 27 अक्टूबर को कैबिनेट विस्तार में बने 4 नए मंत्रियों को हटाने की मांग की। इसके साथ वे मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। सोगामी पर पार्टी नेतृत्व को गुमराह करने और संगठन के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप है।

यूपी में बुलेट ट्रेन चलेगी 3.30 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी

काशी में रेलमंत्री का ऐलान, पीएम ने दी कॉरिडोर को मंजूरी

वाराणसी (एजेंसी)। यूपी में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू होगा। दिल्ली-वाराणसी-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। यह बात रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी में बताई। रेलमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने इसके नॉर्दर्न कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह ट्रेन दिल्ली से चलकर आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। इसके बाद पटना होते हुए गुवाहाटी तक

जाएगी। कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से आगरा का सफर 59 मिनट, कानपुर का 1 घंटे 45 मिनट और लखनऊ का 2 घंटे 12 मिनट में पूरा होगा।

फर्स्ट एसी में शॉवर, विमान जैसी सुविधाओं का अनुभव

ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। यहां बर्थ और केबिन का इंटीरियर ज्यादा लग्जरी रखा गया है। फर्स्ट एसी के बाथरूम में शॉवर की सुविधा भी मिलेगी। सभी कोच में इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल के बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। यात्रियों को सफर के दौरान साफ-सफाई और आराम का बेहतर अनुभव देने की कोशिश की गई है। इस ट्रेन की सबसे खास व्यवस्था यह है कि इसमें पारंपरिक ट्रेनों की तरह एसी और वेटिंग टिकट की सुविधा नहीं होगी। केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर सकेंगे। इससे कोच में निर्धारित क्षमता से अधिक भीड़ नहीं होगी। यात्रियों को अपनी बर्थ पर आराम से सोने और सामान रखने की सुविधा मिलेगी।

काशी को दो नई मेमू ट्रेनों की भी सौगात

वंदे भारत स्लीपर के साथ वाराणसी क्षेत्र को दो नई रेल सेवाओं की भी सौगात मिलेगी। वाराणसी सिटी से राजातालाब के बीच चार जोड़ी मेमू ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों में 12 कोच होंगे। रास्ते में वाराणसी जंक्शन, बनारस, भुलनपुर और हरदत्तपुर स्टेशन पर ठहराव होगा। इससे दैनिक यात्रियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा बनारस से प्रयागराज रामबाग के बीच मेमू सेवा को आगे बढ़ाने की योजना है। इससे दोनों धार्मिक और शैक्षिक शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। इन नई सेवाओं से काशी की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ स्थानीय यात्रियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

बांग्लादेश में भारत के ट्रांजिट कॉरिडोर का विरोध

विपक्षी नेता बोले-देश की जमीन भारत को नहीं देंगे

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में भारत के ट्रांजिट कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। विपक्षी नेता नाहिद इस्लाम ने शुक्रवार को ढाका में एक रैली के दौरान आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार बांग्लादेश में भारत को ट्रांजिट कॉरिडोर देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जमीन भारत को नहीं दी जाएगी। ट्रांजिट कॉरिडोर का मतलब एक देश की जमीन और सड़क का इस्तेमाल

करके दूसरे देश के किसी हिस्से तक सामान पहुंचाना है। इससे दूरी और सामान पहुंचाने में लगने वाला समय कम हो सकता है। नाहिद ने गंगा जल समझौते को लेकर भी सरकार से सख्त रुख अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर समझौते को नए सिरे से करते समय बांग्लादेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, तो लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे।

नाहिद इस्लाम की रैली में भारत विरोधी नारे भी लगे

नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम की अगुआई में तारिक रहमान सरकार के खिलाफ ढाका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शनकारी बढ़ती महंगाई, बिजली संकट और पेट्रोल-डीजल व गैस की कमी से नाराज थे। उन्होंने गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए।

होर्मुज में हमले का नया तरीका, जहाज पर चिपकाया बम

धमाके से इंजन रूम जला, 27 भारतीय मौजूद थे, सभी सुरक्षित

ओमान (एजेंसी)। होर्मुज में गुरुवार को 27 भारतीय क्रू सदस्यों वाले तेल टैंकर लुईस 1 पर हमला हुआ। पनामा के झंडे वाले इस टैंकर के पास एक छोटी नाव पहुंची थी। नाव से आए लोगों ने जहाज के बाहरी हिस्से (हुल) पर दो लिम्पेट माइंस चिपका दीं और वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोनों विस्फोटकों में धमाका हुआ, जिससे इंजन रूम में आग लग गई। इसकी वजह से जहाज का इंजन कुछ समय के लिए बंद हो गया। हालांकि, क्रू ने आग पर काबू पा लिया और जहाज को सुरक्षित कर लिया। हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी

पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि जहाज पर सवार सभी 27 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। किसी को चोट नहीं आई है।

एक दिन में दो तेल टैंकरों पर हमला

29 अक्टूबर को लाइबेरिया के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी अरजानाह पर भी हमला हुआ था। इस जहाज पर दो भारतीय नागरिक सवार थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक, दोनों भारतीय सुरक्षित हैं। इस तरह एक ही दिन में होर्मुज के आसपास दो तेल टैंकरों पर हमले हुए। दोनों जहाजों पर कुल 29 भारतीय नाविक सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से 30 अक्टूबर तक फारस की खाड़ी, होर्मुज और ओमान की खाड़ी में 122 जहाजों पर हमला हुआ।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सरदार पटेल का अखंड भारत और विकसित राष्ट्र का संकल्प

(लेखक - विनोद सिंह 'तकियावाला')

राष्ट्रीय एकता दिवस केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक गौरव और नशामुक्त भारत के निर्माण का सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प है भारत का इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों और सत्ता परिवर्तन की गाथा नहीं है, बल्कि यह त्याग, तपस्या, संघर्ष, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता के निर्माण की अद्भुत यात्रा भी है। इस ऐतिहासिक यात्रा में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं, जिनका योगदान समय की सीमाओं से परे जाकर राष्ट्र की नियति निर्धारित करता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ऐसे ही महान राष्ट्रनायक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिखराव की आशंकाओं के बीच भारत की एकता और अखंडता को साकार कर इतिहास में अपना अमिट स्थान बनाया। उनकी 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन का वास्तविक उद्देश्य उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण करने के साथ यह संकल्प लेना भी है कि जिस अखंड भारत की नींव उन्होंने रखी थी, उसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक स्तर पर और अधिक सशक्त बनाया जाए।

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 'एकता दौड़' का शुभारंभ और देशवासियों को एकता की शपथ दिलाना इसी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा ने उनके ऐतिहासिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह आयोजन केवल औपचारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय भावना को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास है, जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

अखंड भारत के निर्माण में सरदार पटेल का ऐतिहासिक योगदान

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही देश के सामने अनेक गंभीर चुनौतियाँ भी खड़ी थीं। विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक तनाव, विस्थापन और आर्थिक कठिनाइयों के बीच सबसे बड़ी चुनौती देशी रियासतों का भारत में एकीकरण था। उस समय देश में सैकड़ों रियासतें थीं। उनके अलग-अलग राजनीतिक हित और भविष्य को लेकर अनिश्चितता भारत की एकता के सामने गंभीर प्रश्न खड़े कर रही थीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थीं कि विविधताओं से भरा भारत स्वतंत्रता के बाद एकजुट नहीं रह पाएगा।

ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी असाधारण राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीतिक कुशलता, दृढ़ निर्णय क्षमता और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की भावना से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। तत्कालीन रियासतों के एकीकरण में उन्होंने वी.पी. मेनन के सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संवाद, समझदारी, दूरदर्शिता और आवश्यकतानुसार दृढ़ता का परिचय देते हुए उन्होंने अनेक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार साहब ने मात्र 1218 दिनों में अखंड भारत की रचना कर वह कार्य कर दिखाया, जिसे अनेक नेता अपने पूरे जीवनकाल में भी नहीं कर पाते।

सरदार पटेल का योगदान केवल राजनीतिक और भौगोलिक एकीकरण तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय चेतना को एक सूत्र में बाँधने का कार्य भी किया। उनकी दृष्टि में भारत केवल भौगोलिक सीमाओं से निर्मित भूखंड नहीं, बल्कि एक साझा सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा राष्ट्र था। यही कारण है कि आज भी उनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रभावशाली प्रतीक बना हुआ है।

विविधता में एकता ही भारत की वास्तविक शक्ति

भारत की विशेषता उसकी विविधता है। यहाँ अनेक भाषाएँ, बोलियाँ, धर्म, पंथ, वेशभूषाएँ, खान-पान और सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। इसके बावजूद भारत की राष्ट्रीय पहचान एक साझा सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी रही है। अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इसी भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि भाषाई, सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है।

आज वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच इस विचार की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। किसी भी राष्ट्र की मजबूती केवल उसकी आर्थिक समृद्धि या सैन्य क्षमता से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी सामाजिक एकजुटता, आपसी विश्वास और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विविधताओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। संवाद, सहिष्णुता, समावेशी सोच और परस्पर सम्मान के माध्यम से ही ऐसा समाज निर्मित हो सकता है, जहाँ अलग-अलग पहचान रखने वाले नागरिक एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए आगे बढ़ें।

राष्ट्रीय एकता का अर्थ किसी भाषा, संस्कृति या परंपरा को दूसरी पर थोपना नहीं, बल्कि सभी को समान सम्मान और अवसर प्रदान करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है। यही भावना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को विशिष्ट पहचान देती है।

नशामुक्त भारत - विकसित भारत की पहली शर्त

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अमित शाह ने नशामुक्त भारत के संकल्प को विकसित भारत की परिकल्पना से जोड़कर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना का पहला चरण नशामुक्त भारत का निर्माण है। सरकार ने 31 दिसंबर 2029 तक देश को नशे से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उनके अनुसार, नशामुक्त भारत का निर्माण देश के युवाओं और उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा।

यह विषय केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास और मानव संसाधन की गुणवत्ता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी पूँजी उसकी युवा शक्ति, प्रतिभा, ऊर्जा और नवाचार की क्षमता है। यदि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाए तो व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ परिवार, समाज और राष्ट्र की विकास यात्रा भी प्रभावित होती है। नशा व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता को कमजोर करने के साथ सामाजिक अपराध, आर्थिक संकट और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं को भी जन्म देता है।

इसलिए नशामुक्त भारत का संकल्प केवल सरकारी अभियान बनकर नहीं रहना चाहिए। इसमें परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता, खेल एवं रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन, नशे की अवैध तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है। नशामुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है, जब रोकथाम, जागरूकता, उपचार और पुनर्वास को व्यापक सामाजिक अभियान का स्वरूप दिया जाए।

सोमनाथ से राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक

भारत की राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण आधार उसकी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इसी चेतना का ऐतिहासिक उदाहरण है। विदेशी आक्रमणों और विध्वंस के बावजूद इस मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय समाज की अदम्य इच्छाशक्ति, आस्था और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक बना। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की संकल्पना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अमित शाह ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के माध्यम से देश ने सभ्यता और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का अनुभव किया है। यह प्रसंग बताता है कि राष्ट्र निर्माण केवल प्रशासनिक और आर्थिक विकास से पूरा नहीं होता। इसके लिए अपनी ऐतिहासिक स्मृतियों, सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत के प्रति सम्मान भी आवश्यक है। आधुनिक भारत को अपनी सभ्यतागत चेतना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ना होगा।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी - राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक

सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व और योगदान को वैश्विक पहचान दिलाने में गुजरात के केवड़िया स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इस विशाल प्रतिमा की परिकल्पना को आगे बढ़ाया और उसका शिलान्यास किया। आज यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा के रूप में भारत के राष्ट्रीय गौरव और लौह पुरुष के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है।

अमित शाह ने कहा कि लंबे समय तक सरदार पटेल को उनके योगदान के अनुरूप सम्मान नहीं मिला और उन्हें भुलाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन सूर्य के प्रकाश को कोई ढक नहीं सकता। ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का मूल्यांकन राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर उनके वास्तविक योगदान के आधार पर होना चाहिए। सरदार पटेल का राष्ट्र के प्रति समर्पण किसी राजनीतिक दल या विचारधारा की सीमाओं में बाँधा नहीं जा सकता। वे सम्पूर्ण भारत की साझा राष्ट्रीय विरासत हैं। उनके योगदान का सम्मान करना और नई पीढ़ी को उनके विचारों से परिचित कराना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है।

संपादकीय

दवा के दर्द

खाड़ी में अमेरिका-इस्राइल व ईरान के बीच जारी संघर्ष का प्रभाव केवल पेट्रोलियम पदार्थों पर ही नहीं, कृषि से लेकर दवा उद्योग पर भी असर दिखाने लगा है। इस संघर्ष ने अब हिमाचल और हरियाणा के दवा उद्योग को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सर्वविदित है, ये क्षेत्र देश के दवा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से। लेकिन पश्चिमी एशिया में जारी अशांति के चलते, प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति में अचानक गंभीर व्यवधान पैदा हो गया है। दरअसल, इस संकट के मूल में जरूरी फार्मास्यूटिकल अवयवों यानी एपीआई, सॉल्वैंट्स और पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स की कीमतों में भारी वृद्धि होना है। दरअसल, इनमें से कई कच्चे मालों की आपूर्ति पश्चिमी एशिया से होती है या इन देशों से लगते समुद्री मार्गों से होकर भारत पहुंचती है। एक तो इस इलाके में संघर्ष के चलते शिपिंग मार्गों पर भारी दबाव पड़ा है। वहीं ऊर्जा साधनों की कीमतों में अस्थिरता के चलते, कुछ क्षेत्रों में कच्चे माल की कीमतों में तीस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। खासकर पैकेजिंग सामग्री, जो अधिकांशत- पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित होती है, वह भी खासी महंगी हो गई है। जिसके चलते प्रतिस्पर्धा के कारण पहले कम लाभ के मार्जिन पर काम कर रहे दवा उद्योग पर अतिरेक दबाव पड़ गया है। लेकिन इस संकट का दूसरा पहलू यह है कि इस व्यवधान का असर उद्योग पर वित्तीय कारणों से ही नहीं है, बल्कि श्रमिकों से जुड़े कारणों से भी है। दरअसल, इस संकट के बीच प्रवासी श्रमिक भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ईंधन संकट और छोटे एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यक आपूर्ति में बाधा का असर श्रमिकों के दैनिक जीवन और कार्य स्थिरता को लेकर पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों पर अत्यधिक निर्भर फार्मा इकाइयों के लिये यह व्यवधान उत्पादकता में गतिरोध पैदा कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो उद्योग की मजबूती केवल आपूर्ति शृंखला से ही नहीं जुड़ी है बल्कि उनके श्रमिकों के हितों और उनके आत्मविश्वास से भी जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र और हरियाणा के फार्मा क्लस्टर्स पर इसकी दोहरी मार पड़ रही है। जहां एक ओर उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर छोटे निर्माताओं को उत्पादन में कटौती करने अथवा नुकसान उठाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी ओर बढ़ती लागत व वैश्विक परिवहन लागत में वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में ये उद्योग पिछड़ रहा है। बहरहाल, इस संकट ने आयातित कच्चे माल और वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर भारत की निर्भरता की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार की पहल से आयातित कच्चे सामान पर शुल्क में छूट से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोत तलाशने, घरेलू एपीआई उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्रवासी श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। सही मायनों में एक दूर का युद्ध भारत की दवा आपूर्ति और उसके उत्पादकों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है।

चक्रवातों के साये में तटीय भारत का भविष्य

(लेखिका- डॉ. प्रियंका सौरभ)

समुद्र जितना जीवनदायी है, उसका रौद्र रूप उतना ही विनाशकारी हो सकता है। भारत की करीब 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए बेहद अहम है। लेकिन यही तटीय क्षेत्र हर साल चक्रवातों, समुद्री तूफानों, बाढ़ और तटीय कटाव का खतरा भी झेलते हैं। चक्रवात अर्नब ने एक बार फिर तटीय भारत की संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल केवल यह नहीं है कि चक्रवात कब और कहां आएगा, बल्कि यह भी है कि उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। बदलते मौसम के दौर में अब आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने के बजाय पहले से नुकसान कम करने की रणनीति बनानी होगी।

चक्रवातों से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती उनके बदलते स्वरूप और तीव्रता का अनुमान लगाना है। आधुनिक तकनीक और मौसम पूर्वानुमान में सुधार के बावजूद कई बार चक्रवात कम समय में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री जुटाने के लिए बहुत कम समय बचता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें और नदियों में बाढ़ एक साथ तबाही मचा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है।

तटीय क्षेत्रों में कमजोर बुनियादी ढांचा भी बड़ी समस्या है। चक्रवात के दौरान बिजली के खंभे गिर जाते हैं, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और संचार सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। इससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित होते हैं। कई तटीय शहरों में अनियोजित निर्माण, जल निकासी की खराब व्यवस्था और निचले इलाकों में बस्तियों का विस्तार खतरे को बढ़ा रहा है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को बचाने के साथ-साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करना भी बड़ी चुनौती बन जाता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग की पूर्व चेतावनी प्रणाली पहले से बेहतर हुई है, लेकिन चुनौती अब भी यह है कि चेतावनी समय पर हर व्यक्ति तक पहुंचे। समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों, दूरदराज के गांवों और छोटे द्वीपों में रहने वाले लोगों तक सूचना पहुंचाना आसान नहीं है। कई बार लोग चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते या घर और आजीविका छोड़ने के डर से सुरक्षित स्थानों पर जाने में देरी करते हैं। इसलिए केवल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को उसके खतरे और उससे बचने के उपायों के बारे में समझाना भी जरूरी है।

चक्रवात का असर सभी पर समान नहीं पड़ता। गरीब परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन परिवारों की आजीविका खेती, मछली पकड़ने या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है, उनके लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना भी आसान नहीं होता। उन्हें अपनी संपत्ति, पशुओं और रोजगार की चिंता सताती है। चक्रवात के बाद मछली पकड़ने का काम बंद हो जाता है, खेतों में खारा पानी भर जाता है और छोटे कारोबार ठप पड़ जाते हैं। इससे प्रभावित परिवारों के सामने लंबे समय तक आर्थिक संकट बना रहता है।

प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कमजोर होना भी चिंता का विषय है। मैंग्रोव वनों की कटाई, आर्द्रभूमियों का विनाश और समुद्र तटों पर बढ़ता निर्माण चक्रवातों के खतरे को बढ़ाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री लहरों की ताकत कम करने और तटीय इलाकों को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर होने वाला विकास भविष्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना होगा। मौसम विभाग की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के साथ उपग्रहों, डॉप्लर रडार और समुद्री निगरानी तंत्र का विस्तार जरूरी है। चेतावनी केवल मोबाइल संदेशों तक सीमित न रहे। सायरन, सामुदायिक रेडियो, स्थानीय प्रशासन और पंचायतों के माध्यम से भी सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए। चेतावनी स्थानीय भाषा में हो और उसमें यह साफ बताया जाए कि लोगों को क्या करना है और कहां जाना है।

इसके साथ ही तटीय इलाकों में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। चक्रवात आश्रयस्थलों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षित निकासी मार्ग बनाने और अस्पतालों, बिजलीघरों तथा पेयजल व्यवस्था को आपदा के लिहाज से मजबूत करने की जरूरत है। आश्रयस्थलों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नियमित मॉक ड्रिल से लोगों को आपदा के समय सही कदम उठाने का अभ्यास कराया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी है। पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, मछुआरा समितियों और युवाओं को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। स्कूलों में आपदा संबंधी जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाए। स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के जोखिम की बेहतर जानकारी होती है। इसलिए उनकी भागीदारी से राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी बनाए जा सकते हैं।

प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर भी नुकसान कम किया जा सकता है। मैंग्रोव वनों, आर्द्रभूमियों और तटीय वनस्पतियों का संरक्षण किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगे और तटीय विनियमन के नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा मछुआरों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए बीमा, आर्थिक सहायता और आजीविका पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी है, ताकि आपदा के बाद वे दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चक्रवात अर्नब ने यह समझने का अवसर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह बचना संभव नहीं, लेकिन बेहतर तैयारी से उनके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। भारत ने मौसम पूर्वानुमान और लोगों की निकासी के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब जरूरत राहत और बचाव तक सीमित रहने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जो आपदा से पहले ही नुकसान को कम कर सके। आखिरकार, सुरक्षित तट केवल मजबूत इमारतों से नहीं बनते, बल्कि जागरूक नागरिकों, जवाबदेह प्रशासन और संरक्षित पर्यावरण से बनते हैं।

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

व्यक्ति- निर्माण समाज पर निर्भर

व्यक्ति का निर्माण केवल उसी पर नहीं, बहुत कुछ अंशों में समाज पर निर्भर है।इसलिए उसे अपने निर्माण को समाज के निर्माण में देखना है। सफलता का पहला सूत्र है- मूल्यों का परिवर्तन। समाज का निर्माण मूल्यों के परिवर्तन से ही होता है। स्वार्थ और संग्रह, ये दोनों मूल्य जब विकसित होते हैं तब व्यक्ति पुष्ट होता है और समाज क्षीण। क्षीण समाज में समर्थ व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाते। आज का समाज सही अर्थ में क्षीण है। उसे पुष्ट करने के लिए स्वार्थ और विसर्जन के मूल्यों को विकसित करना जरूरी है। इनसे समाज पुष्ट होगा। पुष्ट समाज में समर्थ व्यक्तित्व पैदा होंगे। क्षीण कोई नहीं होगा। मैंने देखा है स्वार्थ और संग्रह परायण समाज ने अनेक प्रकार की क्रूरताओं और अनैतिकताओं को जन्म दिया है। इसे बदलना क्या आज के सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है? सफलता का दूसरा सूत्र है- शक्ति का विकास। शक्ति के दो स्रोत हैं- मानसिक विकास और संगठन। मानसिक विकास के लिए धर्म का अभ्यास और प्रयोग करना जरूरी है। संगठन की शक्ति का विस्फोट इतना हुआ है कि अब इसमें कोई विवाद ही नहीं है। हमारे पूज्य भिक्षु स्वामी ने संगठन का मूल्य दो शताब्दी पूर्व ही समझ लिया था। उनके अनुयायियों को क्या उसे अब भी समझना है। वात्सलता और सहानुभूति को विकसित किए बिना संगठन सुदृढ़ नहीं हो सकता। आज सबकुछ शक्ति-संचय के आधार पर हो रहा है। इसलिए संगठन अब अनिवार्य हो गया है। छोटे-छोटे प्रश्न इस महान कार्य में अवरोध नहीं बनने चाहिए। सफलता का तीसरा सूत्र है- शातौर परिवर्तन का यथार्थ-बोध। कुछ स्थितियां देशकालातीत होती है। उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है, किंतु देशकाल सापेक्ष स्थितियों का देशकाल के बदलने के साथ न बदलना असफलता का मुख्य हेतु है। परिवर्तन के विषय में युवकों का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। बदलना अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है और नहीं बदलना कोई सार्थकता नहीं है। बदलने की स्थिति होने पर बदलना विकास की अनिवार्य प्रक्रिया है।

करोड़ों की मेडिकल शिक्षा, लाखों की नौकरी: डॉक्टर बनेगा या कर्जदार?

(लेखक- सनत जैन)

निजी मेडिकल शिक्षा में बड़े उद्योगपतियों और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों की भागीदारी को लेकर बहस होती रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेजों की फीस किस आधार पर तय होती है? क्या इसका संबंध वास्तविक प्रशिक्षण लागत, अस्पतालों की सुविधाओं, फैकल्टी और विद्यार्थियों को मिलने वाले स्टाइपेंड से है, या मांग और भुगतान क्षमता भी बड़ी भूमिका निभाती है?

भारत में मेडिकल शिक्षा की बढ़ती लागत अब केवल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की चिंता नहीं, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल है। डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए परिवार वर्षों की बचत लगा देते हैं, संपत्ति तक बेच देते हैं और कई बार बैंक से भारी कर्ज लेते हैं। इसके बावजूद महंगी डिग्री हासिल करने के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। निजी मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस कुछ मामलों में दो से तीन करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। मुंबई के नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की बताई गई फीस इसका उदाहरण है, जहां एमडी डर्मेटोलॉजी और रेडियो डायग्नोसिस जैसी विशेषज्ञताओं की फीस बेहद ऊंची है। वहीं, मध्य प्रदेश के श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज, इंदौर और मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में भी अलग-अलग विशेषज्ञताओं के लिए फीस में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हालांकि, वास्तविक खर्च का आंकलन करते समय आधिकारिक फीस सूची, अतिरिक्त शुल्क और पूरे पाठ्यक्रम की लागत को अलग-अलग देखना जरूरी है।

समस्या केवल बहुत अधिक फीस तक सीमित नहीं है। एमबीबीएस की पढ़ाई पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी हर डॉक्टर को तुरंत अच्छी नौकरी नहीं मिलती। शुरुआती वेतन कई मामलों में सीमित रहता है। इसी तरह, एमडी या एमएस करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा अन्य पदों पर मिलने वाला वेतन हर जगह एक जैसा नहीं होता। डेढ़ से ढाई लाख रुपये मासिक वेतन भी दो करोड़ रुपये के कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज की भरपाई के लिए पर्याप्त साबित होगा या नहीं, यह खर्च, कर, पारिवारिक जिम्मेदारियों और ऋण की शर्तों पर निर्भर करता है। यदि कोई डॉक्टर हर महीने एक लाख रुपये बचाता है, तो दो करोड़ रुपये के बराबर बचत जमा करने में लगभग 16 वर्ष आठ महीने लगेंगे। दो लाख रुपये मासिक बचत की स्थिति में भी करीब आठ वर्ष चार महीने लगेंगे। इस गणना में ब्याज, महंगाई और निवेश की वैकल्पिक लागत शामिल नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कमाई और वास्तविक बचत के बीच कितना बड़ा अंतर होता है।

निजी मेडिकल शिक्षा में बड़े उद्योगपतियों और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों की भागीदारी को लेकर बहस होती रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेजों की फीस किस आधार पर तय होती है? क्या इसका संबंध वास्तविक प्रशिक्षण लागत, अस्पतालों की सुविधाओं, फैकल्टी और विद्यार्थियों को मिलने वाले स्टाइपेंड से है, या मांग और भुगतान क्षमता भी बड़ी भूमिका निभाती है? इसका जवाब पारदर्शी आंकड़ों से ही मिल सकता है। महंगी शिक्षा का दबाव डॉक्टरों पर आर्थिक तनाव बढ़ा सकता है। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर महंगी डिग्री वाला डॉक्टर अनैतिक व्यवहार करेगा। फिर भी मरीजों को अनावश्यक जांच, दवाओं और प्रक्रियाओं के आर्थिक बोझ से बचाना स्वास्थ्य व्यवस्था की अनिवार्य जिम्मेदारी है।

इस स्थिति में सरकार को निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस का स्वतंत्र लागत ऑडिट कराने, पूरे पाठ्यक्रम का शुल्क पहले से घोषित करने और अतिरिक्त शुल्क की स्पष्ट जानकारी देने की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और कम ब्याज वाले शिक्षा ऋण के विकल्प भी बढ़ाए जाने चाहिए। डॉक्टर की मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञ बनने का अवसर केवल आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आखिरकार, मेडिकल शिक्षा में किया गया निवेश तभी सार्थक होगा, जब डॉक्टर को सम्मानजनक भविष्य मिले और मरीज को सुलभ इलाज। सवाल सीधा है- भारत में डॉक्टर बनने का रास्ता प्रतिभा और मेहनत से तय होगा या परिवार की आर्थिक हैसियत से?

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सरकार ने कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली ।

सरकार ने घरेलू कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने और उत्पादन लागत कम करने के लिए कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट की अवधि दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दी है। यह छूट पहले 31 अक्टूबर तक प्रभावी थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस फैसले से कपड़ा और परिधान क्षेत्र की उत्पादन लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ कपड़ा बनाने वाली कंपनियों और अंततः उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह कदम बाजार में कपास की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे घरेलू कपड़ा उद्योग, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विस्तार से घरेलू किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है।

बाइनैंस पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला, 6.3 अरब की क्रिप्टो चोरी

उत्तर कोरिया पर संदेह, एक्सचेंज ने ग्राहकों के नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया

नई दिल्ली ।

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनैंस को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा है, जिसमें हैकरों ने अनुमानित 6.3 अरब डॉलर (लगभग 52,000 करोड़ रुपये) की क्रिप्टोकरेंसी चुरा ली।

इस घटना ने वैश्विक क्रिप्टो बाजार को हिला दिया है और विश्लेषकों ने इस चोरी के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ होने का आरोप लगाया है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय डकैतियों में से एक बताया जा रहा है। बाइनैंस पर हुआ यह जटिल हमला गुरुवार देर रात को लगभग 20 मिनट के भीतर अंजाम दिया गया, जिसने कंपनी के वॉलेट को हैकरों के नियंत्रण वाले वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। हमले की खबर सामने आते ही क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और बाइनैंस ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए निकासी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया। स्टेबलकॉइन जारी करने वाली कुछ कंपनियों ने चोरी की गई संपत्तियों में से लगभग आधी, यानी करीब 3 अरब डॉलर, को फ्रीज कर दिया है। अमेरिकी ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनियों और संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के अनुसार, इस हमले के तौर-तरीके उत्तर कोरिया की विशिष्ट हैकिंग इकाई द्वारा पहले किए गए बड़े साइबर हमलों से मिलते-जुलते हैं। 2025 में हुए बायबिट एक्सचेंज हमले के लिए भी एफबीआई ने उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराया था, हालांकि उत्तर कोरिया ऐसे आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है।

बाइनैंस ने तुरंत घोषणा की है कि वह ग्राहकों के नुकसान की भरपाई अपने कोष से करेगी, जिसके लिए उसने लगभग 6.34 अरब डॉलर अलग रखे हैं। कंपनी के पास सुरक्षा में सेंधमारी की स्थिति में ग्राहकों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1 अरब डॉलर का बिटकॉइन रिजर्व फंड भी है। बाइनैंस एफबीआई और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले की गहन जांच कर रहा है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर बताया कि निकासी सेवाएं अगले 48 घंटों में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इस सेंधमारी के बाद बिटकॉइन छह सप्ताह के निचले स्तर 76,368 डॉलर पर आ गया, जबकि ईथर भी 3 फीसदी से अधिक गिरकर 2,178 डॉलर रह गया।

एयू एसएफबी पर डेटा लीक का खतरा

हैकर्स का संवेदनशील जानकारी चुराने का दावा

नई दिल्ली ।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक संभावित डेटा लीक के बड़े खतरे में है। स्कारलेट ग्रुप नामक हैकिंग समूह ने बैंक के ग्राहकों और आंतरिक रिकॉर्ड से आधार, पैन, केवाईसी, सिबिल स्कोर जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने का दावा किया है। हैकर्स ने बैंक को बातचीत के लिए छह दिन की समय सीमा दी है और डेटा सार्वजनिक करने की धमकी दी है। बैंक ने हालांकि अपने मुख्य सिस्टम को सुरक्षित बताया है, पर सेल्सफोर्स ऐप से जुड़े सीमित डेटा ब्रीच की संभावना स्वीकार की है। हैकर्स का दावा है कि लीक हुए डेटा में ग्राहकों के आधार, पैन, केवाईसी, सिबिल स्कोर, बैंक स्टेटमेंट और ऋण संबंधी विवरण, साथ ही आंतरिक कंपनी रिकॉर्ड भी शामिल हैं। इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बैंक ने पुष्टि की है कि केवल उसके वाहन वित्त ग्राहकों से जुड़ी सीमित जानकारी प्रभावित हुई है। बैंक का कहना है कि मुख्य बैंकिंग सिस्टम अप्रभावित है और सभी सेवाएं सामान्य हैं; मामले की गहन जांच जारी है। ग्राहकों को अनजान कॉल/मैसेज से सावधान रहने, ओटीपी/पिन/पासवर्ड साझा न करने, और नियमित रूप से लेनदेन की जांच करने को कहा गया है। संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना बैंक को देने की सलाह दी गई है।

उतार-चढ़ाव भरे सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार ने मारी बाजी

फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले ने बाजार को नई दिशा दी

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा। वैश्विक कारकों और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के दबाव में सप्ताह की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले ने बाजार को नई दिशा दी। शुरुआती झटकों और बीच में दबाव के बावजूद, निवेशकों के भरोसे ने बाजार को मजबूत वापसी करने में मदद की, और प्रमुख सूचकांकों ने लगभग 2 फीसदी की साप्ताहिक बढ़त के साथ सप्ताह का अंत किया। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को जोरदार गिरावट के साथ हुई, जहां सेंसेक्स 500 अंक से अधिक और निफ्टी 185 अंक से अधिक लुढ़क गया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपये में कमजोरी ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। हालांकि, शुरुआती बिकवाली के बाद बाजार ने गजब की वापसी करते हुए निचले स्तरों से लगभग 2 फीसदी की रिकवरी दर्ज की, और सेंसेक्स 482 अंक तथा निफ्टी 153 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मंगलवार को बाजार एक बार फिर वैश्विक दबाव में दिखा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेड के

फैसले से पहले निवेशकों की सतर्कता के कारण गैप-डाउन ओपनिंग हुई। हालांकि, दिन के अंत तक बाजार ने अपनी अधिकांश गिरावट को कम कर दिया और लगभग सपाट बंद हुआ। बुधवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी शेयरों में नुकसान के साथ-साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले का इंतजार बाजार पर हावी रहा। सेंसेक्स 352 अंक और निफ्टी 50 अंक से अधिक टूटकर बंद हुए।

सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट

- सोना 1.42 लाख, चांदी 1.85 लाख के पर

नई दिल्ली ।

भारतीय सर्राफा बाजार में शे निवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों को खरीदारी का एक सुनहरा अवसर मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी तेज बिकवाली का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर दिखा। चांदी लगभग 11 महीने के अपने सबसे निचले स्तर 1,85,504 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,540 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यह गिरावट केवल आज की नहीं है, बल्कि शुक्रवार को भी राष्ट्रीय राजधानी में चांदी 8,300 रुपये गिरकर 1,90,200 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, जबकि सोना 1,300 रुपये की कमी के साथ 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। जानकारों के अनुसार, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, वैश्विक महंगाई की चिंताएं और अमेरिका में ब्याज दरों पर सख्त रुख की आशंका इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं। डॉलर की मजबूती और निवेशकों की रणनीति भी कीमती धातुओं पर दबाव डाल रही है। हालांकि, खरीदारों को सलाह दी जाती है कि आभूषणों की कुल लागत में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जुड़ते हैं।

पीआई इंडस्ट्रीज ने भारत में विकसित पहला कीटनाशक अणु पेश किया

छह नवंबर से होगा व्यावसायिक इस्तेमाल

नई दिल्ली ।

पीआई इंडस्ट्रीज ने भारत में विकसित किए गए पहले कीटनाशक अणु पायोक्सानिलिप्रोल को लॉन्च किया है। एंथ्रानिलिक डायमाइड वर्ग का यह अभिनव उत्पाद 6 नवंबर को रबी सत्र के दौरान बाजार में उतारा जाएगा, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य धान और मक्का की फसलें होंगी। कंपनी के एक अे धिकारी ने बताया कि पायोक्सानिलिप्रोल एक दशक से अधिक के गहन शोध का परिणाम है। इसे विशेष रूप से भारतीय कृषि परिस्थितियों और किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। धनतेरस के अवसर पर इसकी शुरुआत में, कंपनी पहले चरण में धान और मक्का पर केंद्रित रहेगी, जिसे बाद में अन्य फसलों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआत में इसे रबी सत्र के दौरान उन चुनिंदा फसलों और क्षेत्रों में सीमित मात्रा में उतारा जाएगा जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, न कि एक साथ देशभर में। पीआई इंडस्ट्रीज का लक्ष्य केवल बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों के साथ मिलकर काम करना है। इसके तहत लगभग एक लाख किसानों को नमूने उपलब्ध कराकर, खेतों में इसका प्रदर्शन किया जाएगा और उनसे प्रतिक्रिया ली जाएगी।

चीन के शेयर बाजार में भारी गिरावट

निवेशकों को 329 लाख करोड़ का नुकसान

भारत और अमेरिका के शेयर बाजार भी चीन की राह पर?

नई दिल्ली ।

दुनिया के शेयर बाजारों में इन दिनों जिस तरह की अनिश्चितता दिखाई दे रही है। उसने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और आर्थिक विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। चीन, अमेरिका और भारत जैसे बड़े बाजारों में उतार-चढ़ाव केवल घरेलू अर्थव्यवस्था का मामला नहीं रह गया है। इसका असर वैश्विक पूंजी, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ रहा है।

चीन के शेयर बाजार में 52 सप्ताह तक लगातार गिरावट और 329 लाख करोड़ रुपये के नुकसान निवेशकों को होने की बात सामने आ रही है।

चीन के शेयर बाजार की गिरावट ने सभी शेयर बाजारों में हलचल पैदा कर दी है। 25 अक्टूबर की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, मई के बाद से चीनी शेयर बाजार का मूल्य लगभग 3। 5 लाख करोड़ डॉलर घट चुका है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 329 लाख करोड़ रुपये होता है। 30 अक्टूबर की रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक, चीन का सीएसआई 300 सूचकांक लगातार 12वें सप्ताह गिरावट की ओर था। पिछले 12 सप्ताह में लगभग 14 प्रतिशत बाजार टूट चुका था। यह चीन के शेयर बाजार की कमजोरी का महत्वपूर्ण संकेत है।

चीन की गिरावट के आर्थिक कारण

चीन की अर्थव्यवस्था में घरेलू खपत की कमजोरी, रियल एस्टेट क्षेत्र का संकट, कंपनियों के मुनाफे में गिरावट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (द्ध) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों का अत्यधिक मूल्यांकन प्रमुख कारण माना जा रहा है। निवेशकों को आशंका है, कंपनियों का उत्पादन और निर्यात बढ़ने के बावजूद घरेलू मांग तथा वास्तविक मुनाफे में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। तकनीकी कंपनियों में भारी निवेश के बावजूद भविष्य में उससे कितना लाभ होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।

भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली चिंता का विषय

भारत के शेयर बाजार मे सबसे बड़ी चुनौती विदेशी संस्थागत निवेशकों (स्वच्छ) की लगातार बिकवाली है। विदेशी मुद्रा भंडार भी चिंता का विषय बना हुआ है। अक्टूबर के पहले 25 दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 48,056 करोड़ रुपये निकाल लिए थे। वर्ष 2026 में कुल निकासी 3.08 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है । सितंबर में भी विदेशी निवेशकों ने 35,861 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। इसके पीछे अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर 5 प्रतिशत से अधिक ब्याज मिलने, डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और एशियाई तकनीकी कंपनियों में निवेश के बढ़ते आकर्षण मुख्य कारण हैं। विदेशी निवेशकों के लिए भारत की तुलना में दूसरे बाजारों में निवेश अधिक आकर्षक और सुरक्षित दिखाई दे रहा है।

जिओ की लिस्टिंग से मिली बाजार को राहत

भारतीय शेयर बाजार में अक्टूबर के अंतिम दिनों में कुछ सुधार जरूर आया है। 30 अक्टूबर को सेंसेक्स 0.42 प्रतिशत और निफ्टी 0.51 प्रतिशत बढ़कर बंद हुए। पूरे अक्टूबर में सेंसेक्स में 2.7 प्रतिशत और निफ्टी में 1.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई।

महाराष्ट्र में लंबे अभियान के दौरान 18.94 करोड़ का खाद्य तेल जब्त

80 कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित, एफडीए आयुक्त ने मिलावटखोरों को चेताया

मुंबई ।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य तेल में मिलावट और घटिया गुणवत्ता के खिलाफ चलाए गए सात महीने के अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इस दौरान करीब 18.94 करोड़ रुपये मूल्य का 28,753 क्विंटल खाद्य तेल जब्त किया और 80 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। एफडीए ने एक अप्रैल से 29 अक्टूबर के बीच राज्य भर में 1,089 निरीक्षण किए। इन छापों में खाद्य तेल निर्माताओं, री-पैकिंग करने वालों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निशाना बनाया गया।

प्रयोगशाला जांच के लिए 1,660 नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 485 की रिपोर्ट आ चुकी है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने चेतावनी दी है कि मिलावटी या असुरक्षित तेल के निर्माण, भंडारण या बिक्री पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने राज्य के सात मंडलों में 80 लाइसेंस निलंबित किए हैं, जिनमें छत्रपति संभाजीनगर में सर्वाधिक 27 और पुणे में 22 लाइसेंस शामिल हैं।

जब्त तेल की बात करें तो पुणे में सबसे अधिक 19,551 क्विंटल और छत्रपति संभाजीनगर में 5,736 क्विंटल तेल बरामद हुआ। हालांकि, मूल्य के हिसाब से छत्रपति संभाजीनगर में 8.34 करोड़ रुपये का तेल जब्त किया गया, जो सबसे अधिक है। लाइसेंस निलंबन के प्रमुख कारणों में दोबारा इस्तेमाल किए गए टिन, बिना लेबल वाले कंटेनरों में तेल बेचना, स्वच्छता मानकों का उल्लंघन और लेबलिंग नियमों की अनदेखी शामिल है। निलंबित प्रतिष्ठान इस अवधि में कोई भी खाद्य कारोबार नहीं कर पाएंगे।

जतिन कुमार नायक ने संभाला इरेडा के चेयरमैन का पदभार

नई दिल्ली।

जतिन कुमार नायक ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार संभाल लिया है। कंपनी ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। नायक इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे। कंपनी के अनुसार नायक को तीन दशक से अधिक का व्यापक और विविध अनुभव है। वह आरईसी की अनुषंगी कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड में मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने एनएचपीसी, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में भी काम किया है। उनका अनुभव बिजली क्षेत्र के साथ-साथ खनन एवं धातु जैसे संसाधन-आधारित उद्योगों में भी रहा है। नायक ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। इससे पहले मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने उन्हें यह जिम्मेदारी देने के लिए मंजूरी दी थी।

सरकार के सिंगल यूज उपकरण प्रतिबंध पर अस्पतालों का कड़ा विरोध

प्रमुख अस्पताल समूहों ने सरकार को सौंपा ज्ञापन, डायलिसिस समेत कई सेवाएं होंगी प्रभावित

नई दिल्ली ।

देश के बड़े अस्पताल समूहों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एसोसिएशनों ने सरकार के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है, जिसमें एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों के दोबारा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उनकी चिंता है कि इस निर्णय से जटिल बीमारियों के इलाज का खर्च 25 से 75 फीसदी तक बढ़ सकता है और डायलिसिस जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित होंगी। अस्पतालों ने कहा है कि पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहे स्वास्थ्य क्षेत्र की मुश्किलें इससे और बढ़ेंगी। नारायण हेल्थ, मणिपाल हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, के आईएमएस हॉस्पिटल्स और मेदांता सहित कई बड़े अस्पताल समूहों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न स्वास्थ्य एसोसिएशनों के साथ मिलकर सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने मांग की है कि एक बार इस्तेमाल होने वाले सभी मेडिकल उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय, कुछ चुनिंदा उपकरणों को तय सुरक्षा मानकों के तहत दोबारा इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। दरअसल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने 16 अक्टूबर को एक निर्देश जारी कर उन चिकित्सा उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जिन्हें निर्माता कंपनियों ने केवल एक बार इस्तेमाल के लिए बनाया है।

फ्रांस के जेवियर नियल को वोडाफोन समूह में हिस्सेदारी खरीदने की मिली मंजूरी

नई दिल्ली ।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने फ्रांसीसी उद्योगपति जेवियर नियल को ब्रिटेन स्थित वोडाफोन समूह पीएलसी में 16.2 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण नियल की पारिवारिक निवेश कंपनी वेगा एसएएस के माध्यम से किया जाएगा। सीसीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार, नियल अपनी पारिवारिक निवेश कंपनी वेगा एसएएस के जरिए यह हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। वेगा, फ्रांस के कानून के तहत पंजीकृत एक सरलीकृत संयुक्त शेयर बाजार की कंपनी माया एसएएस की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। जेवियर नियल फ्रांस की दूरसंचार कंपनी इलियड के संस्थापक भी हैं, जो उन्हें दूरसंचार क्षेत्र का एक अनुभवी खिलाड़ी बनाती है। यह उल्लेखनीय है कि अधिग्रहणकर्ता वेगा एसएएस की भारत में कोई व्यावसायिक उपस्थिति या गतिविधि नहीं है। वहीं, वोडाफोन समूह भारत में अपनी इकाई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के माध्यम से मोबाइल और फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर, वोडाफोन समूह यूरोप और अफ्रीका के प्रमुख बाजारों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस प्रस्तावित सौदे को अपनी अंतिम मंजूरी की पुष्टि की है, जिससे वोडाफोन समूह में एक महत्वपूर्ण शेयरधारक के रूप में जेवियर नियल की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है।

लायंस और सरकार का गैस विवाद अब मध्यस्थता से सुलझेगा-सुप्रीम कोर्ट

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस की कथित चोरी से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली ।

उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे लगभग 14,750 करोड़ रुपये के गैस विवाद को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यायालय ने इस जटिल मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है और पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह विवाद कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पड़ोसी ओएनजीसी गैस ब्लॉक से कथित तौर पर गैस निकालकर रिलायंस के ब्लॉक में पहुंचाने से संबंधित है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में मध्यस्थता का रास्ता तब चुना, जब उसने पाया कि दोनों पक्षों के बीच कोई आपसी सहमति वाला समाधान नहीं निकल पा रहा था। न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति देसाई को ऐसे जटिल व्यावसायिक विवादों को सुलझाने का व्यापक अनुभव है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को यह भी अनुमति दी है कि वे मध्यस्थ की सहायता के लिए एक-एक विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकते हैं। रिलायंस की ओर से अदालत को बताया गया कि कंपनी मध्यस्थता के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों पक्ष मध्यस्थ के सामने लिखित और मौखिक रूप से अपना पक्ष रख सकेंगे और उन्हें न्यायमूर्ति देसाई से संपर्क कर बैठक तथा सुनवाई का सुविधाजनक कार्यक्रम तय करने को कहा गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी, जिसमें मध्यस्थता की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

यह मामला रिलायंस और उसके सहयोगी कंपनियों की उस अपील से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिलायंस के पक्ष में आए 14,750 करोड़ रुपए के पिछले मध्यस्थता फैसले को रद्द कर दिया था।

विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में की भारी बिकवाली, 22,012 करोड़ के शेयर बेचे

घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 62,220 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश किया

नई दिल्ली ।

अक्टूबर महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय शेयर बाजार से 22,012 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे उनकी इस साल की कुल बिकवाली 2.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। हालांकि, एफपीआई की इस लगातार बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार मजबूत बने रहे, जिसका मुख्य श्रेय घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की रिकॉर्ड खरीदारी और प्राथमिक बाजार में आए दमदार आईपीओ को जाता है। आंकड़ों के अनुसार, जहां एफपीआई ने सेकेंडरी बाजार से बड़ी निकासी की, वहीं उन्होंने प्राथमिक बाजार, जिसमें आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) शामिल हैं, के जरिये 12,902 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह पिछले 15 महीनों में प्राथमिक बाजारों में उनका सबसे बड़ा निवेश है, जिसने सेकेंडरी बाजार में बिकवाली के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद की। इस बीच, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने अक्टूबर के दौरान 62,220 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे बाजार को अभूतपूर्व समर्थन मिला। इसी के परिणामस्वरूप, सेकेंडरी बाजार में लगातार बिकवाली के बावजूद बेंचमार्क निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्रमशः 1.9 फीसदी और 2.7 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। प्राथमिक बाजार में इस मजबूती का एक प्रमुख कारण अक्टूबर में आए 13 आईपीओ थे, जिनमें जियो प्लेटफॉर्म्स का 30,187.65 करोड़ रुपये का आईपीओ भी शामिल था। विश्लेषकों का मानना है कि सेकेंडरी बाजार से एफपीआई की लगातार निकासी के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण हैं। इनमें जापानी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि से पूंजी का बाहर जाना, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं, कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और मार्जिन पर दबाव प्रमुख हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

तुम्हें कितने मार्क्स मिले...?

पेपर का रिजल्ट आने पर अपने बच्चे से कभी न पूछें ये सवाल

यह बात सच्ची है कि जब आप अपने बच्चे से अक्सर 'तुम्हें कितने मार्क्स मिले?' ये सवाल पूछते हैं, तो यह कई तरह से उनकी सेल्फ़-वर्थ, सिखने की प्रक्रिया और मनोधर्म पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज हम आपको बताते हैं कि ये सवाल बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

क्यों यह सवाल नुकसान पहुंचाता है

जब सबसे पहला सवाल ये होता है कि 'कितने अंक आए?', तो बच्चे को यह संदेश जाता है कि अंक = मूल्य = आपकी योग्यता। पर वास्तव में 'अंक' सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम हैं, व्यक्ति की सम्पूर्ण क्षमता या गुण नहीं। उदाहरण के लिए, एक लेख कहता है कि यह हो सकता है कि बच्चों को यह महसूस हो जाए कि उनका पूरा मूल्य सिर्फ उनकी ग्रेड्स से तय होता है। जब यह सवाल बार-बार पूछा जाए, तो बच्चे में यह डर बन सकता है कि अगर अंक कम आए तो उन्हें मम्मा-पापा की नाराज़गी या शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। यह दबाव उनकी पढ़ाई, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

सिखने की प्रक्रिया पर ध्यान कम देना

दिए गए मार्क्स के पीछे क्या हुआ- जैसे तैयारी कैसे हुई, कौन-सी चीज कठिन लगी, किस तरीके से समझा जा सकता था, इन पर कम ध्यान जाता है। परिणाम पर ज्यादा फोकस होने से बच्चों में 'स्कोर करने की रणनीति' बन सकती है बजाय 'समझने की रणनीति' के। यदि संवाद का मुख्य आधार सवाल 'कितने अंक?' हो जाए, तो बच्चे हो सकता है कि उस बातचीत को अपेक्षा-पूर्ति के रूप में देखें- न कि खुली बातचीत के रूप में। इससे पिता-माता-बच्चा के बीच भरोसा कम हो सकता है।

बेहतर तरीका — क्या-क्या पूछा जा सकता है

- 'तुम्हारी एक्साम के दौरान सबसे कठिन क्या लगा? उस पर काम कैसे कर सकते हैं?'
- 'क्या तुमको लगता है तुमने उस विषय में यह तरीके आजमाए? अगर नहीं, तो अगली बार कैसे करोगे?'
- 'क्या वो हिस्सा था जिसमें तुमने अच्छा किया? उस पर हम कैसे और सुधार कर सकते हैं?'
- 'पढ़ाई के अलावा तुम्हें क्या-क्या मज़ेदार लगा आज स्कूल में?'

ऐसे सवाल बच्चों की सोचना, भावनाओं को समझने और संवाद बढ़ाने में मदद करते हैं।

सिर्फ कुछ मिनटों में बनाएं ये पांच टेस्टी सैंडविच, बनाने का तरीका भी है बेहद आसान

शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, जिसे सैंडविच खाना पसंद न हो। तो अगर आपको सैंडविच खाना पसंद है, तो ये खबर आपके लिए खास होने वाली है। चाहे आप ऑफिस जा रहे हों, बच्चों के टिफिन की तैयारी कर रहे हों या घर पर कुछ हल्का और टेस्टी खाना चाहते हों—सैंडविच हर मौके के लिए परफेक्ट ऑप्शन माना जाता है।

ऐसे में आज हम आपको पांच तरह के स्वादिष्ट सैंडविच की रेसिपी बताने जा रहे हैं जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर बना सकते हैं। ये न सिर्फ खाने में लाजवाब हैं बल्कि हेल्दी और एनर्जेटिक भी हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हें बनाने का आसान तरीका और खास टिप्स जिससे आपके सैंडविच बनें बिल्कुल कैफे स्टाइल!

1. वेज ग्रिल सैंडविच

ये सैंडविच बनाना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो ब्रेड पर बटर लगाएं, उसमें टमाटर, खीरा, आलू, और चटनी लगाएं। अब इसे सैंडविच मेकर में गोल्डन ब्राउन होने तक ग्रिल करें। इसे चटनी और कैचअप के साथ परोसें।

2. पनीर टिक्का सैंडविच

पनीर टिक्का सैंडविच खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को मसालों और दही में मेरिनेट करें। इसके बाद इसे इसे ब्रेड के बीच में रखकर ग्रिल करें और पुदीना चटनी के साथ परोसें।

3. एग मेयो सैंडविच

अगर आपको अंडे खाना पसंद है तो आप उबले अंडे को कद्दूकस करके उसमें मेयोनेज को मिक्स करें। दोनों चीजों को मिक्स करें और फिर नमक, काली मिर्च डालें और टोस्टेड ब्रेड पर लगाएं। बस इसे फिर ग्रिल कर लें और कैचअप के साथ परोसें।

4. चीज कॉर्न सैंडविच

ये सैंडविच ज्यादातर हर किसी को पसंद आता है। ये सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले स्वीट कॉर्न को उबाल लें। अब इसमें चीज और थोड़ा ओरिगेनो मिलाएं। अब इसे इसे ब्रेड में भरकर ग्रिल करें। ये सिंपल सा सैंडविच बच्चों से लेकर बड़े भी खूब चाव से खाते हैं।

5. स्पाइसी चटनी सैंडविच

जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये सैंडविच कमाल का है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड पर हरी चटनी फैलाएं। इस हरी चटनी को तीखा ही रखें। अब चटनी फैलाने के बाद टमाटर और प्याज रखें। आखिर में इसे हल्का टोस्ट करें और गर्मागर्म सर्व करें।

बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चे की बेहतर तैयारी के लिए अभिभावक करें ये काम

जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए अभिभावकों को भी कुछ तरीके अपनाने चाहिए, ताकि बच्चा बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम ला सके।

10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चे के लिए बोर्ड परीक्षा एक अहम पड़ाव होता है, जो उनके भविष्य को तय करने में मदद करता है। अच्छे अंक आने पर बेहतर कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति और करियर के लिए क्षेत्र तय करने में मदद मिलती है। ऐसे में भारत के अधिकतर सभी स्कूलों,कोचिंग क्लासेज बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करते हैं।

माता-पिता अपने बच्चे की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे अधिक चिंतित होते हैं। ऐसे में वह बच्चे पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन इसका असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है और अतिरिक्त दबाव उन्हें परेशान कर सकता है। बोर्ड परीक्षा बच्चों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होती है और इसमें अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए अभिभावकों को भी कुछ तरीके अपनाने चाहिए, ताकि बच्चा बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम ला सके।

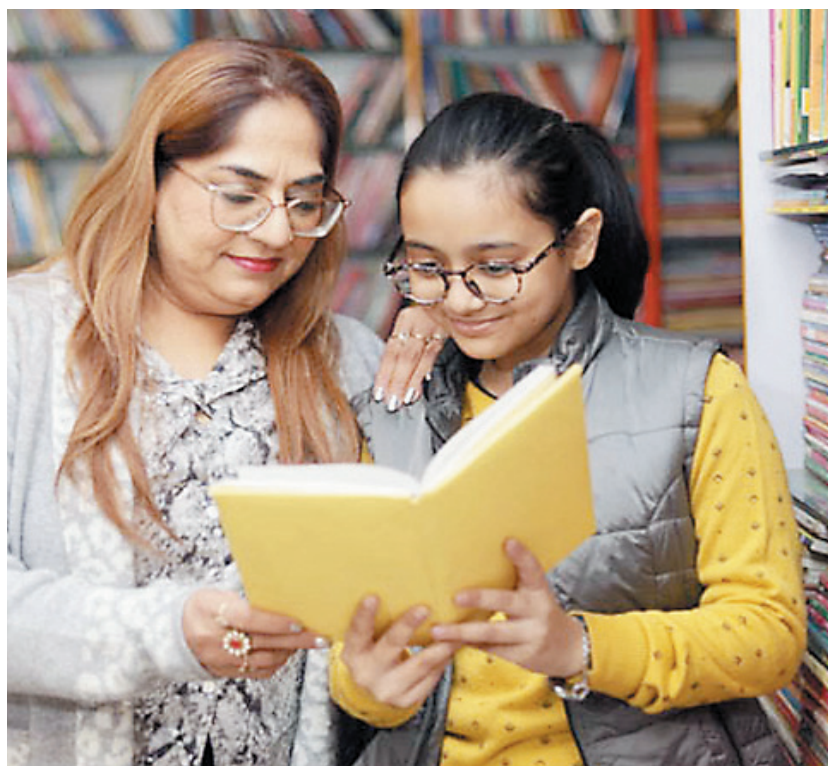

प्रोत्साहित करें

बच्चा दबाव में तब आता है, जब माता पिता अपनी चिंता अत्यधिक जाहिर करते हैं, वो भी नकारात्मक तरीके से। उन पर दबाव बनाने के बजाए माता पिता को बच्चे को परीक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही बच्चे के छोटे-छोटे प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करें।परीक्षा को जीवन-मरण का प्रश्न बनाने की बजाय इसे एक सीखने का अवसर मानें।

पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करें

बच्चे के साथ मिलकर एक प्रभावी टाइम टेबल तैयार करें। टाइमटेबल ऐसा हो ताकि पढ़ाई और आराम के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। कठिन विषयों को अधिक समय दें और पिछले साल के प्रश्न पत्र और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान करें।

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें

इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा मानसिक रूप से परेशान न हो। उसका उत्साहवर्धन करने का प्रयास करें। ऐसी बातें करें जो उसे उत्साहित करें ना कि निराश करें। जैसे 'तुम यह कर सकते हो' और 'मैं तुम्हारे साथ हूं' आदि बातें कहें। बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से न करें।

परिणाम को लेकर ज्यादा चिंता न करें

बच्चे को यह समझाएं कि मेहनत का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। परीक्षा के बाद भी उसे यह भरोसा दिलाएं कि आपका प्यार और समर्थन उसके साथ है। परिक्षा में बेहतर अंक को भविष्य के लिए एकमात्र रास्ता न बनाएं।

नियमित ब्रेक और नींद का ध्यान रखें

दिनभर पढ़न से बच्चा होनहार नहीं हो जाएगा। जरूरी है कि हर एक दो घंटे की पढ़ाई के बाद उसे 10-15 मिनट का ब्रेक मिले। इस ब्रेक में वह दिमाग को फ्रेश करें। शारीरिक गतिविधि करे ताकि उसके दिमाग को आराम और सेहत दुरुस्त रह सके। इसके साथ ही नींद बेहतर जरूरी है। बच्चे को कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

खानपान का ध्यान रखें

बच्चे को पौष्टिक भोजन दें, जिसमें फल, सब्जियां, नट्स, और प्रोटीन शामिल हो। जंक फूड देने से बचें। ये सेहत के लिए तो नुकसानदायक होता ही है, एकाग्रता भी भंग करता है। परीक्षा से ध्यान भटकाने वाले कारकों को कम करें, जैसे बच्चे के मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करें। घर का माहौल ऐसा हो जहां वह पढ़ाई के लिए ध्यान केंद्रित कर सके और शांत वातावरण में मन लगा कर पढ़ सके।

रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान दें

परीक्षा के करीब आते-आते बच्चे को पूरे सिलेबस का रिवीजन करने के लिए प्रेरित करें। समय सीमा के साथ मॉक टेस्ट दें ताकि बच्चे को परीक्षा का अनुभव हो सके।

आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें

बच्चे को समस्याओं को खुद हल करने की आदत डालें। जब बच्चा किसी प्रश्न में अटका हो, तब उसे मार्गदर्शन दें, लेकिन उसे पूरी तरह आप पर निर्भर न बनाएं।

बच्चों में जोड़ों के दर्द के 7 संकेत, आज नजरअंदाज किया तो उम्र भर रहेंगे परेशान

बच्चों में जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें केवल उम्रदराज लोगों में नहीं, बल्कि छोटे बच्चों में भी हो सकती हैं। कई बार माता-पिता इसे सामान्य बढ़ने का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि ये दर्द बार-बार हों या रात में बढ़ जाएं, तो ये

जोड़ों की समस्या का संकेत हो सकता है। यहां बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा बताए गए 7 प्रमुख संकेत दिए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

रात में बढ़ने वाला दर्द

अगर बच्चे को दिन में ठीक रहता है लेकिन रात को दर्द बढ़ जाता है, तो यह सामान्य नहीं है। ऐसा दर्द सूजन या जोड़ों में सूक्ष्म संक्रमण का संकेत हो सकता है।

चलने या दौड़ने में कठिनाई

यदि बच्चा अचानक लंगड़ाने लगे, धीरे चले या दौड़ने से बचे, तो ये संकेत हैं कि उसके जोड़ों में दर्द या जकड़न (ह्यह्लह्लद्धद्धड्डद्गह्यह्य) हो सकती है।

सूजन या लालिमा

किसी एक या अधिक जोड़ों में सूजन, लालपन या गर्माहट महसूस होना सूजन (द्वड्डद्धद्यड्डद्धड्डह्लद्धश्ड्ड) का संकेत है। यह आर्थराइटिस या संक्रमण से भी हो सकता है।

सुबह उठते ही जकड़न

यदि बच्चा सुबह उठते ही अपने हाथ-पैरों को मोड़ने या सीधा करने में परेशानी बताता है, तो यह जोड़ों में सूजन या आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है।

किसी विशेष जोड़ में बार-बार दर्द

अगर दर्द हर बार एक ही घुटने, टखने या कोहनी में हो रहा है, तो यह केवल थकान नहीं, बल्कि जोड़ों की कोई आंतरिक समस्या हो सकती है।

बुखार या थकान के साथ दर्द

अगर जोड़ों का दर्द बुखार, कमजोरी या भूख न लगने के साथ हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह संक्रमण या ऑटोइम्यून बीमारी का संकेत हो सकता है।

बच्चे का खेलने से बचना

यदि बच्चा पहले की तरह खेलना, कूदना या चढ़ना-उतरना छोड़ दे, तो यह दर्द से बचने की कोशिश हो सकती है।

कब डॉक्टर को दिखाए

अगर बच्चे का दर्द 2 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, जोड़ों में सूजन या बुखार आ जाए या फिर बच्चा लंगड़ाने लगे या चलने से बचे तो डॉक्टर को जरूर दिखाए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों के जोड़ों के दर्द को 'द्दह्म्श्2द्बद्वद्द श्चड्डद्बद्व' मानकर टालना ठीक नहीं। जल्दी जांच कराने पर समस्या का इलाज सरल और प्रभावी हो सकता है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और हल्की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के जोड़ों को मजबूत रखते हैं।

शुरू हो गई हैं सर्दियां, बनाकर तैयार करें ये पांच तरह के लड्डू ताकि न हो तबियत खराब

सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को अतिरिक्त पोषण और गर्माहट की जरूरत होती है। इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी अक्सर कमजोर पड़ जाती है, जिससे सर्दी-जुकाम जल्दी हो सकती है। ऐसे में घर पर बने देसी लड्डू न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। पारंपरिक तरीके से बनाए गए लड्डू शरीर को एनर्जी, गर्मी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं।

सर्दी के मौसम में कुछ खास तरह के लड्डू पाचन को बेहतर बनाते हैं, जोड़ों के दर्द से राहत देते हैं और शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर आप ठंड में स्वस्थ और एक्टिव रहना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इन देसी लड्डुओं को जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं ऐसे पांच तरह के लड्डू जो सर्दियों में आपकी तबीयत खराब होने से बचा सकते हैं।

तिल-गुड़ के लड्डू

तिल और गुड़ का मेल सर्दियों में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये शरीर को गर्म रखता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है।

गोंद के लड्डू

गोंद से बने लड्डू जोड़ों के दर्द और ठंड से होने वाली कमजोरी में फायदेमंद होते हैं। इसमें घी, मेवा और गेहूं का आटा मिलाकर बनाया जाता है जो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है।

मेथी के लड्डू

मेथी के लड्डू सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। महिलाओं के लिए ये खासतौर पर फायदेमंद माने जाते हैं क्योंकि ये हॉर्मोनल बैलेंस को भी सपोर्ट करते हैं।

मूंगफली के लड्डू

मूंगफली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसके लड्डू ठंड के मौसम में ऊर्जा प्रदान करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। गुड़ के साथ मिलाकर खाने से ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों बन जाते हैं।

सूखे मेवे के लड्डू

बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और खजूर से बने लड्डू विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये शरीर को ताकत देते हैं और स्किन ग्लोइंग बनाए रखते हैं। तो आप चाहें तो इसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान में एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 10 की मौत

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गुरुवार को एक एंबुलेंस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। हादसा थारपारकर जिले के नगरपारकर इलाके में हुआ। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक, एंबुलेंस दानो धंधल स्थित एक बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र से महिला को जिला अस्पताल मीठी ले जा रही थी। प्रसव के बाद जटिलताएं होने के कारण महिला को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाना था। थारपारकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आरिफ अजीज जाफरी ने बताया कि अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें संबंधित महिला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस के अंदर चालक द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर को इधर-उधर करते समय उसमें विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आगे की जांच चल रही है। इससे पहले, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के राजनपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कराची से डेरा गाजी खान जा रही एक यात्री बस निर्माण कार्य वाले राजमार्ग पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा रेस्क्यू 1122 के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों ने बस की रफ्तार तेज होने की आशंका जताई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

बोस्निया में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा: यूरोपीय संघ के शांति मिशन के चार कर्मियों की मौत, 11 घायल; जांच शुरू

साराजेवो, एजेंसी। बोस्निया-हर्जेगोविना के उत्तरी इलाके में यूरोपीय संघ के शांति मिशन (ईयूफोर) का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार चार कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। ईयूफोर ने बताया कि सभी घायलों की हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। हादसा ब्रचको शहर के आसपास हुआ। इटली का सीएच-47 चिनूक हेलीकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल था। इसी दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार पोर्टल क्विक्स ने घटनास्थल की तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में एक मैदान में पड़ा दिखाई दे रहा है। ईयूफोर ने बताया कि दुर्घटना की गहन और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। घटना से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी बाद में साझा की जाएगी। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी आम नागरिक को चोट नहीं आई। आसपास की नागरिक संपत्ति, इमारतों और वाहनों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

यमन के हूतियों ने सऊदी अरब के तेल, हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों पर किया हमला

सना, एजेंसी। यमन के हूती ग्रुप ने सऊदी अरब पर हमले का दावा किया है। हूती ने कहा कि उसने सऊदी अरब में तेल सुविधाओं, हवाई अड्डों और एक सैन्य ठिकाने पर छह मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने हूति-संचालित 'अल-मसीराह टीवी' पर प्रसारित एक बयान में कहा कि तीन बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में स्थित 'रास तानूरा रिफाइनरी' और 'अब्काइक' में सऊदी अरामको की सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसके अलावा, देश के लाल सागर तट पर स्थित 'राबिग रिफाइनरी' को भी निशाना बनाया गया। सरिया ने बताया कि दो अन्य ऑपरेशन्स में सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित 'किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे' पर मिसाइलों से, और पूर्वी प्रांत के दम्मम में स्थित 'किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे' पर ड्रोन से हमला किया गया। हूती के सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि इस हमले के कारण हवाई यातायात बाधित हुआ। याह्या सरिया ने यह भी बताया कि हूती ग्रुप ने दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र नजरां स्थित सऊदी सैन्य बलों के 'कमांड सेंटर' को भी निशाना बनाया है। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में कई सैनिक और अधिकारी हताहत हुए हैं। इसके अलावा, सरिया ने कहा कि ये हमले यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्रों पर सऊदी अरब की ओर से हाल ही में किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं।

इजराइल चुनाव- सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे आइजनकोट

तीन विपक्षी नेताओं से मुलाकात की; बोले- नेतन्याहू चुनाव को बदनाम कर रहे

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल में चुनाव के बाद विपक्षी नेता गादी आइजनकोट सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। उन्होंने डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान, बियाचाद के प्रमुख नफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता यायर लैपिड से मुलाकात की है। आइजनकोट ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी चुनाव नतीजों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिला। चुनाव में अब तक आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, जबकि नेतन्याहू के खेमे को 53 सीटें मिली हैं। इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का समर्थन जरूरी है। वहीं, अरब पार्टियों को 19 सीटें मिली हैं। ऐसे में किसी भी खेमे के पास बहुमत नहीं है। सरकार बनाने के लिए दोनों खेमों को दूसरे दलों का समर्थन जुटाना होगा।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को चुनाव में जीत की बधाई दी

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यरूशलम में मुलाकात के दौरान। यह तस्वीर 19 अप्रैल 2026 की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और इजराइल के प्रधानमंत्री

नेतन्याहू यरूशलम में मुलाकात के दौरान। यह तस्वीर 19 अप्रैल 2026 की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चुनाव में जीत की बधाई दी है। उन्होंने लिकुड पार्टी की जीत को बड़ी कामयाबी बताया। मिलेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर लिखा कि लिकुड एक बार फिर इजराइल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है।

मिलेई ने कहा कि नेतन्याहू ने विरोधी सर्वे और चुनावी अनुमानों के बावजूद अपने नेतृत्व की ताकत दिखाई है। अर्जेंटीना और इजराइल पश्चिमी मूल्यों को चुनौती देने वाली ताकतों के खिलाफ रणनीतिक साझेदार बने रहेंगे। रिपोर्ट- नेतन्याहू के सहयोगी ने आइजनकोट को क्क्रू पद का ऑफर दिया नेतन्याहू के सहयोगी दल यूनाइटेड टोरा जूडिज्म ने विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया है। चैनल 12 न्यूज के मुताबिक, पार्टी इसके बदले हरेदी यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने की मांग कर रही है। पार्टी के पास 7 सीटें हैं। वह आइजनकोट की सरकार में शामिल हुए बिना उसे समर्थन दे सकती है और संसद में उसके खिलाफ वोट नहीं करेगी। पार्टी के एक नेता ने कहा, 'नेतन्याहू से अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। उनके साथ हमारा गठबंधन खत्म हो चुका है।' हालांकि, आइजनकोट सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा के पक्ष में हैं, जबकि यूनाइटेड टोरा जूडिज्म इसका विरोध करती है। ऐसे में दोनों के बीच सहमति बनना मुश्किल हो सकता है। आइजनकोट बोले- नेतन्याहू चुनाव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे गादी आइजनकोट ने नेतन्याहू पर चुनाव के नतीजों को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लिकुड पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी, इसलिए चुनाव पर सवाल उठा रही है। आइजनकोट ने साफ किया कि वे संसद (नेसेट) की बैठक तय समय पर होने से रोकने नहीं देंगे। इजराइल की 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में पूर्ण बहुमत के लिए 61 सीटों की दरकार है, लेकिन मौजूदा नतीजों ने किसी भी एक गुट को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है: प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी ब्लॉक को 53 सीटें मिली हैं। विपक्षी गठबंधन: गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के खाते में 48 सीटें आई हैं। अरब पार्टियां व अन्य: अरब पार्टियों ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। किसी भी खेमे के पास अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण सत्ता की चाबी अब छोटे दलों और स्वतंत्र गुटों के रुख पर टिक गई है।

'तुम बहुत खराब दिख रहे हो': अपनी सेहत पर सवाल सुनते ही भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, पत्रकार से कहा- खुद को फिट करो

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक पत्रकार पर निजी हमला किया। दरअसल, जब पत्रकार ने ट्रंप की सेहत और कंसास तथा आयोवा में होने वाली चुनाव रैलियों को रद्द करने के उनके फैसले के बारे में सवाल किया। इस पर ट्रंप ने उनके शारीरिक रूप-रंग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, खुद को फिट रखने की सलाह दी। यह बहस तब शुरू हुई जब पत्रकार ने पूछा कि क्या कंसास न जाने का ट्रंप का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि देश भर में हफ्तों तक चुनाव प्रचार करने के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं है? ट्रंप अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने पत्रकार से कहा, 'ओह, ऐसा सवाल पूछने के लिए आप बीमार हैं। आप बीमार हैं। जब रिपोर्टर ने साफ किया कि वह केवल राष्ट्रपति का हाल-चाल पूछ रहा था, तो ट्रंप ने उस व्यक्ति के शारीरिक रूप-रंग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कुछ पल के लिए पत्रकार की नकल उतारी और उसके सवाल को दोहराया। ट्रंप ने कहा, 'इस आदमी को देखो। इसका शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं है।' जब उनसे फिर पूछा गया कि क्या उनकी तबीयत ठीक है, तो राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि उनका स्वास्थ्य एकदम सही है। उन्होंने कहा, 'मैं पिछले दो हफ्तों से खुद पर नजर रख रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं।' इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति पर एक और निजी हमला किया। ट्रंप ने टिप्पणी की, 'तुम बहुत भद्दे लग रहे हो। अपने शरीर को ठीक करो। तुम बहुत ही खराब दिख रहे हो।' यह तीखी बहस तब हुई जब ट्रंप ने कैनसस और आयोवा में सप्ताहांत के लिए तय अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया। इन जगहों पर मंगलवार को होने वाले मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में रिपब्लिकन पार्टी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। ये रैलियां शनिवार को कैनसस के सलीना और रविवार को आयोवा के डुबुक में होनी थीं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें कि ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कैनसस जाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने इस राज्य में रिपब्लिकन सीनेटर रोजर मार्शल की जीत की संभावनाओं पर भरोसा जताया। बाद में रिपब्लिकन नेशनल कमिटी ने आयोवा रैली के रद्द होने की भी पुष्टि कर दी। ट्रंप के कैंपेन फंडिंग ग्रुप, 'क्क्र इंक' ने बताया कि ट्रंप खुद वहां जाने के बजाय, चुनाव के दिन से पहले कैनसस और आयोवा समेत कम से कम 19 राज्यों में 'टेली-रैलियों' (फोन या ऑनलाइन माध्यम से होने वाली रैलियों) की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे। इन मध्यावधि चुनावों से यह तय होगा कि क्या रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों में अपना मामूली नियंत्रण बनाए रख पाते हैं या नहीं। इन दो कार्यक्रमों को रद्द करने के बावजूद, उम्मीद है।

भूटान में शिंताफू हिमनद झील फटी, असम-बंगाल में बाढ़ का अलर्ट

थिम्पू, एजेंसी। भूटान के गासा जिले में स्थित शिंताफू हिमनद झील के फटने के बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों के लिए एक विशेष परामर्श जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि संकोश नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो सकती है। यह घटना बृहस्पतिवार शाम को भूटान के गासा जिले के लाया गेवोग में लुंगो स्थित वाकिला पर्वत के नीचे मौजूद शिंताफू झील में हुई। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क करने के लिए सायरन बजाए गए, जबकि प्रभावित इलाके के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। शिंताफू झील भूटान की 17 अत्यधिक संवेदनशील और संभावित रूप से खतरनाक हिमनद झीलों में शामिल है। यह झील भूटान के पुनातसंगछु नदी बेसिन में स्थित है। यह नदी भारत में प्रवेश करने पर संकोश नदी के नाम से जानी जाती है और उत्तरी बंगाल और असम के बड़े हिस्से से होकर गुजरती है। अचानक जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती बस्तियों, मवेशियों, फसलों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दोनों राज्यों का स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

अमेरिका के ओरेगन में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर, प्रमुख राजमार्ग बंद : ओरेगन , एजेंसी। ओरेगन में पोर्टलैंड के दक्षिण-पश्चिम में एक छोटे हवाई अड्डे के पास बृहस्पतिवार दोपहर (अमेरिकी समय) दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के कारण एक प्रमुख राजमार्ग बंद करना पड़ा। यामहिल काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार, मैकमिनविल एयरपोर्ट के कुछ किलोमीटर पूर्व में यह दुर्घटना हुई। अधिकारियों के पास हेलीकॉप्टरों में सवार लोगों की संख्या या उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओरेगन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने बताया कि दुर्घटना के कारण डेटन के 1.6 किलोमीटर पश्चिम में हाईवे 233 बंद कर दिया गया है।

अमेरिका के 10 सैन्य विमान इजराइल में उतरे

ट्रम्प की पश्चिम एशिया के टॉप कमांडर से मुलाकात, ईरान पर फिर हमले की तैयारी

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते में उसके 10 से ज्यादा सैन्य मालवाहक विमान दक्षिणी इजराइल के एयरबेस पर उतरे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रम्प ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सेना के पश्चिम एशिया कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, कूपर ने ईरान पर संभावित सैन्य हमले के विकल्पों की जानकारी दी। बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन भी मौजूद थे।

अमेरिकी चुनाव के बाद ईरान पर हमले की तैयारी

अमेरिका और इजराइल 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद ईरान पर फिर हमले करने की योजना बना

रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, दोनों देश छोटी लेकिन तेज सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। इसमें ईरान के ऊर्जा ठिकानों, परमाणु केंद्रों और मिसाइलों व ड्रोन के भंडार को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि, ट्रम्प अभी सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला भी ले सकते हैं। सऊदी, कतर, कुवैत में भी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा अमेरिका विमान ट्रैकिंग डेटा पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका के ज्यादातर सैन्य मालवाहक विमान टेक्सास के बिग्स आर्मी एयरफील्ड से रवाना हुए थे। ये इजराइल के नेवातिम और ओवदा एयरबेस पहुंचे। इसके अलावा अमेरिका के कई सैन्य विमान सऊदी अरब, कतर, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी पहुंचे हैं। इन विमानों में क्या सामान लाया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका संभावित युद्ध से पहले पश्चिम एशिया में अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत कर रहा है। अमेरिका टेक्सास से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की एक बैटरी भी पश्चिम एशिया भेज रहा है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक, ईरान ने इजराइल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। साथ ही वह अगले हफ्ते होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में भी दखल देने की तैयारी कर रहा था। अखबार ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इसके लिए एजेंटों की भर्ती और अमेरिकी चुनाव सिस्टम को हैक करने वाले साइबर समूह बनाने की कोशिश की गई।

पश्चिम एशिया: होर्मुज में बढ़ रहा है समुद्री खतरा? टैंकर पर हमले के बाद अलर्ट, ब्रिटिश एजेंसी ने दी जानकारी

खासाब, ओमान , एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर एक छोटी नाव के जरिए हमला किया गया। नाव से टैंकर के ढांचे पर दो विस्फोटक उपकरण लगा दिए गए, जिससे इंजन रूम में आग लग गई और जहाज कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया। यूकेएमटीओ के अनुसार, यह घटना गुरुवार को लगभग 2212 यूटीसी पर, ओमान के खासाब से लगभग 25 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में हुई। शुक्रवार को जारी एक अपडेट में, यूकेएमटीओ ने बताया कि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। यूकेएमटीओ ने कहा, 'रिपोर्ट से पता चलता है कि एक छोटी नाव टैंकर के

बाईं ओर (पोर्ट साइड) आई और उसने पानी की सतह के ऊपर टैंकर के ढांचे पर दो विस्फोटक उपकरण लगा दिए।' इसमें आगे बताया गया कि इसके बाद हुए विस्फोटों से इंजन रूम में आग लग गई, जिससे जहाज कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया। समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने कहा, 'अब आग बुझ चुकी है और जहाज अपने अगले गंतव्य बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है।' शुरुआत में यूकेएमटीओ को एक रिपोर्ट मिली थी कि बाहर जा रहे एक टैंकर में आग लग गई है।

उस समय घटना के कारण, चालक दल की स्थिति, नुकसान के आकलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ताजा अपडेट के बाद, यूकेएमटीओ ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा, 'जब तक अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, तब तक जहाजों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी से आगे बढ़ें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना यूकेएमटीओ को दें।' यह घटना ऐसे समय में हुई है जब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले समुद्री यातायात को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने इस जलमार्ग पर अपना नियंत्रण जताते हुए व्यावसायिक जहाजों को उन क्षेत्रों से न गुजरने की चेतावनी दी है, जिन्हें वे प्रतिबंधित और असुरक्षित मानते हैं। ईरान की नौसेना के जनसंपर्क विभाग ने सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के माध्यम से एक बयान जारी कर दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में एक प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजर रहे एक टैंकर में, एक नौसैनिक खदान (नेवल माइन) से टकराने के बाद आग लग गई। बयान में कहा गया है।

अटलांटा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका ने समुद्री मार्गों, ऊर्जा और सप्लाई चेन पर दिया जोर

अटलांटा , एजेंसी। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार को जी20 विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए अटलांटा पहुंचे। अमेरिका के अनुसार, इस बैठक में एनर्जी, सप्लाई चेन और समुद्री रास्तों को खुला रखने पर फोकस रहेगा। ये ऐसे मुद्दे हैं, जो भारत के तेल, एलएनजी और उर्वरक आयात के लिए बेहद अहम हैं। वे इस बैठक के दौरान क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बैठक से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'जरूरी संकटों से निपटने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को बिना किसी खतरे या टोल के व्यापार के लिए खुला रखने का साझा संकल्प है। यह एनर्जी संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही उर्वरक और भोजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। '

यह बैठक विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी में हो रही है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हो रहे व्यवधान के कारण भारत के लिए एनर्जी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, 'एनर्जी दुनिया भर में आर्थिक विकास की बुनियाद है और इसकी पहुंच सस्ती और भरपूर होनी चाहिए। अधिकारी ने कहा, 'क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन एनर्जी सुरक्षा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद जरूरी है और अन्य सप्लाई चेन भी आवश्यक हैं, खासकर उर्वरक,

एलएनजी, तेल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अन्य कच्चे माल के लिए।' अधिकारी ने कहा, 'अटलांटा में बातचीत एनर्जी और सप्लाई चेन चुनौतियों पर चर्चा करने और आर्थिक सुरक्षा पर भू-राजनीतिक तनाव के प्रभाव से निपटने के तरीकों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी। ' नई दिल्ली में बुधवार को इस दौरे की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, 'विदेश मंत्री 30 से 31 अक्टूबर तक अटलांटा में होने वाली जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान, वे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगे और अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ' ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि वह इस साल की तीसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका, भारत और जापान के समकक्षों से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ईयू के नेतृत्व वाले 'नो फीस / नो टोल्स' संकल्प में शामिल हो गया है, जो गैरकानूनी फीस और टोल का विरोध करता है।

रूस ने अमेरिका प्रतिबंधों के खिलाफ क्यूबा का किया समर्थन

मॉस्को , एजेंसी। अमेरिका प्रतिबंधों के खिलाफ रूस ने क्यूबा का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह क्यूबा पर लगे अमेरिकी आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को हटाने की कोशिश में अपना समर्थन देना जारी रखेगा। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इन प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 130 वोट पड़े, 17 वोट इसके खिलाफ थे, जबकि 25 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मंत्रालय ने बताया कि रूस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही कहा कि वोट के नतीजों ने यह साबित किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हवाना (क्यूबा) के खिलाफ लगाए गए इन अवैध और अमानवीय प्रतिबंधों की लगभग सर्वसम्मति से और दृढ़तापूर्वक निंदा की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि इस साल क्यूबा पर आर्थिक और सैन्य दबाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। इसके साथ ही एनर्जी ब्लॉकेड ने आम नागरिकों को अस्तित्व बचाने के संकट के कगार पर ला खड़ा किया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर क्यूबा में सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ढह

जाती है, तो वहां से बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में एक बड़ा प्रवासन संकट पैदा हो सकता है। वहीं, रूस ने अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा कर रही क्यूबा की सरकार और वहां के लोगों के साहस की प्रशंसा की। रूस ने कहा कि भारी अमेरिकी दबाव के बावजूद, हवाना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर मॉस्को का सैद्धांतिक रुख पहले जैसा ही है। उसने क्यूबा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने का वादा किया, ताकि इस द्वीप देश पर लगे प्रतिबंधों को जल्द से जल्द, पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के हटाया जा सके। इस बीच, भारत ने बुधवार को एक बार फिर उन कानूनों को खारिज कर दिया जो दूसरे देशों की संप्रभुता पर बुरा असर डालते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें क्यूबा पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की काउंसलर सौम्या नायर ने कहा कि नई दिल्ली महासभा की उस अपील का समर्थन करती है, जिसमें सभी देशों से कहा गया है कि वे 'ऐसे कानूनों और नियमों को खारिज करें, जिनका असर देश की सीमाओं के बाहर तक होता है क्यूबा के खिलाफ आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग वाले प्रस्ताव पर मतदान से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा, 'भारत, असेंबली की उस अपील को दोहराता है जिसमें सभी देशों से कहा गया है कि वे ऐसे कानूनों और उपायों को लागू करने से बचें, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप, ऐसे कानूनों और उपायों को रद्द करें और अमान्य घोषित करें।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

फाइव स्टार होटल के स्विमिंग पूल में करंट से दो विदेशी नागरिकों की मौत

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हलसूरु स्थित प्रतिष्ठित पांच सितारा कॉनराड होटल में शुक्रवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। होटल की तीसरी मंजिल पर बने स्विमिंग पूल में करंट लगने की आशंका के बीच दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। उन्हें बचाने की कोशिश में एक अमेरिकी पर्यटक और होटल का लाइफगार्ड भी घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय स्विमिंग पूल में मौजूद जर्मनी और स्लोवाकिया के दो नागरिक संदिग्ध परिस्थितियों में करंट की चपेट में आ गए। शुरुआती जांच में बिजली का करंट लगना मौत की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद ही हो सकेगी। हादसे के दौरान दोनों विदेशी नागरिकों को बचाने की कोशिश में 41 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मैथ्यू डेसेंटिस और 28 वर्षीय राहुल तिवारी भी घायल हो गए। मैथ्यू होटल में ठहरे हुए अमेरिकी पर्यटक हैं, जबकि राहुल तिवारी कॉनराड होटल में पूल अटेंडेंट और लाइफगार्ड के रूप में काम करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-7 की जांच के दिए आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने मामले की जांच के आदेश देने के साथ ही शिकायतों की पड़ताल और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। दरअसल, निर्वाचन आयोग के समक्ष मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा किए जाने को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। आरोप है कि कुछ मामलों में बड़ी संख्या में फॉर्म जमा किए गए, लेकिन संबंधित मतदाताओं के नाम नहीं हटाए गए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले से जुड़ी याचिकाएं रखी गईं। इनमें एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 32 फॉर्म-7 जमा किए जाने का आरोप भी शामिल है। अदालत ने निर्वाचन आयोग से शिकायतों की जांच कर आवश्यक सुधार करने और रिपोर्ट देने को कहा है।

महाराष्ट्र में दो बार कांपी धरती, चार पड़ोसी देशों में भी लगे झटके

- सभी जगहों पर भूकंप की तीव्रता अलग-अलग रही, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में शनिवार को भूकंप के झटके लगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में शनिवार की आधी रात को धरती दो बार कांपी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक पहला भूकंप रात 12 बजकर 54 मिनट पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। इसके बाद रात 1 बजकर 30 मिनट पर एक बार फिर झटके लगे और इस दूसरे भूकंप की तीव्रता 2.1 मापी गई। दोनों भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र के पालघर में ही था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आए इन दो भूकंपों के अलावा अफगानिस्तान, चीन के तिब्बत क्षेत्र, म्यांमार और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए यानी कुछ ही घंटों में एशिया के अलग-अलग हिस्सों में धरती कांपी। हालांकि इन सभी जगहों पर दर्ज भूकंप की तीव्रता अलग-अलग रही। राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र समेत अन्य देशों में आए भूकंप में अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत के अलावा अफगानिस्तान और चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी भूकंप दर्ज किए गए। अफगानिस्तान में शनिवार सुबह 3 बजकर 48 मिनट 15 सेकंड पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.0 मापी गई।

विकसित भारत की कल्पना का रास्ता नशामुक्त भारत निर्माण से होकर गुजरता है

-अमित शाह ने सरदार पटेल की जयंती पर दोहराया नशामुक्त भारत का लक्ष्य

नई दिल्ली , एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश को 31 दिसंबर 2029 तक पूरी तरह नशामुक्त बनाने का लक्ष्य फिर दोहराया। उन्होंने देशवासियों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की और कहा कि पीएम मोदी की विकसित भारत की कल्पना का रास्ता नशामुक्त भारत के निर्माण से होकर गुजरता है। शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश को नशे से पूरी तरह मुक्त करना युवाओं के भविष्य और राष्ट्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने दावा किया कि इस साल 31 मार्च तक देश नक्सलवाद के साये से पूरी तरह बाहर निकल चुका है और अब नशामुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में लिए गए कई बड़े फैसलों और हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि जब भारत आजाद हुआ था, तब दुनिया के कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि देश बिखर जाएगा, लेकिन आजादी के बाद के मात्र 1,218 दिनों में सरदार पटेल ने वह काम कर दिखाया, जिसे दुनिया असंभव मान रही थी।

शाह ने कहा कि जिस काम को नेताओं का एक समूह मिलकर भी शायद पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, उसे सरदार पटेल ने पूरा कर दिखाया। उन्होंने भारत को एकजुट करने का ऐतिहासिक काम किया और रियासतों का विलय कर एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। सरदार पटेल ने जिस भारत की कल्पना की थी और जिसे एकजुट किया, वही देश आज पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ खड़ा है। गृह मंत्री ने देश के युवाओं को नशे से बचाकर उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई।

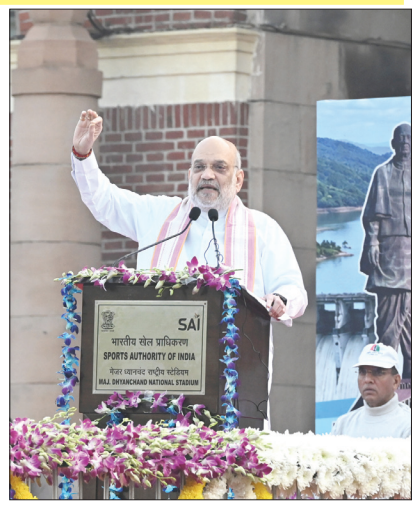

कांग्रेस की रैली का विरोध कर रहे व्यापारियों ने की राहुल से अपील

नई दिल्ली, एजेंसी। दिवाली के ठीक पहले दिल्ली के व्यापारियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब आगामी 1 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की एक बड़ी रैली का ऐलान हुआ। व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने राहुल गांधी से इस रैली को स्थगित करने की पुरजोर अपील की है। सीटीआई ने अपने संदेश में कहा कि राहुल गांधी अक्सर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, लेकिन व्यापारियों की अपनी दुकानें भी ग्राहकों के साथ आपसी विश्वास और प्यार के आधार पर ही चलती हैं। इसलिए त्योहारों के इस पीक सीजन में व्यापारियों की रोजी-रोटी और व्यापार इस रैली की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। संगठन के चेयरमैन ने कहा कि चांदनी चौक की परांठे वाली दुकान, खारी बावली के मसाले, सदर बाजार की चूड़ी-बिंदी, चांदनी चौक का लहंगा, दरियागंज का एसी, चावड़ी बाजार की सामग्री और करोल बाग की मशहूर कुल्फी जैसी सैकड़ों पुरानी और प्रसिद्ध दुकानें असल में जनता के लिए मोहब्बत की ही दुकानें हैं, जिन पर हर दुकान के माध्यम से दर्जनों परिवारों का गुजारा होता है। व्यापारी संगठनों ने रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 20 बड़े थोक बाजारों में विरोध स्वरूप पोस्टर लगाने का ऐलान किया है। संगठन का तर्क है कि धनतेरस से ठीक चार दिन पहले होने वाली इस रैली में भारी भीड़ और हजारों गाड़ियों के आने से पूरी दिल्ली में भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे रामलीला मैदान के आसपास के इन प्रमुख बाजारों में ताले लटकने की नौबत आ जाएगी। व्यापारियों ने चिंता जताई है कि यदि इस व्यस्त त्योहारी सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई और बाजार बंद हुए, तो इससे लगभग 20 लाख व्यापारियों का हजारों करोड़ रुपये का दिवाली व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा और लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा।

रामलीला मैदान में होने वाली रैली से पहले रिजिजू ने पूछे कांग्रेस से सवाल

- सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडिया गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उससे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देने की चुनौती भी दी है।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा, कांग्रेस को बुनियादी सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 44 सीटें कैसे मिलीं, जबकि उस समय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उसकी ही सरकार ने की थी?

उनका दूसरा सवाल था कि 2024 में जब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, तब कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव में हार का सामना कैसे करना पड़ा? उन्होंने सवाल किया, क्या कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और 2014 से 2026 के बीच सरकारें बनाने के लिए माफी मांगेंगे?

रिजिजू ने अगले सवाल में मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों, मृत व्यक्तियों, दूसरी जगह चले गए लोगों और दोहरे नामों को हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख पूछा। अंत में रिजिजू का सवाल था, क्या 1952-56, 1958-61, 1965-66, 1983-84, 1987-88, 1993, 1995 और 2002-2004 के दौरान किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भी अवैध थे? इसी के साथ ही रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, एक परिवार की पार्टी बाहरी ताकतों के साथ मिलकर संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

1 नवंबर की दिल्ली रैली में शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी

-सांसद संजय सिंह ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की अपनी मांग दोहराई

नई दिल्ली, एजेंसी । आम आदमी पार्टी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घोषणा की है कि पार्टी इस रैली में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वह पहले ही साफ कर चुकी है कि वह इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस बयान के साथ आप ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता के दावों के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने का संकेत दिया है। हालांकि, संजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर देशभर में 13 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिसे उन्होंने वोट चोरी का एक

सुनियोजित प्रयास बताया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया। संजय सिंह ने कहा कि यदि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी यानी तार्किक विसंगतियों के नाम पर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए गए हैं, तो पश्चिम बंगाल में हुआ हालिया चुनाव अवैध है और उसे रद्द किया जाना चाहिए।

उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में ही मतदाता सूची से 40 हजार नाम हटाए गए हैं। इस आधार पर उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को भी रद्द करने की मांग की। संजय सिंह ने बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत उन सभी राज्यों में नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की, जहां इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं। उनकी यह मांग लोकसभा और विधानसभा, दोनों चुनावों पर लागू होती है। उनका कहना है कि जिन चुनावों में ऐसी गड़बड़ियां हुई, उन्हें रद्द कर दोबारा कराया जाना चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे और जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे।

जम्मू-कश्मीर में कैबिनेट फेरबदल से विधायकों की नाराजगी आई सामने

- फारूक और उमर अब्दुल्ला को ज्ञापन सौंपेंगे चार विधायक, पार्टी नहीं छोड़ने पर सहमति

जम्मू, एजेंसी । जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई हैं। पार्टी के कम से कम 18 विधायकों ने श्रीनगर में लोलाब के विधायक कैसर जमशेद लोन के आवास पर एक बैठक की। 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद हुई इस बैठक को पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी के सामने आने से जोड़कर देखा जा रहा है।

मंत्रिमंडल विस्तार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार विधायकों अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कालू को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था, जबकि निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को बाहर कर दिया गया। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ विधायक ने इसे केवल दोस्ताना लंच बताया और किसी राजनीतिक महत्व से इनकार किया।

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक विधायकों ने कैबिनेट व्यवस्था और पार्टी के संगठनात्मक कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही सर्वसम्मति से तय किया गया कि कोई भी विधायक पार्टी नहीं छोड़ेगा और न ही पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगा।

चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सौंपेगा ज्ञापन

सूत्रों के अनुसार, विधायकों ने नजीर अहमद के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाने का फैसला किया है। यह प्रतिनिधिमंडल पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ज्ञापन सौंपेगा। इसमें कैबिनेट व्यवस्था में बदलाव और दो साल से अधिक समय से मंत्री पद पर बने नेताओं को हटाने की मांग शामिल हो सकती है।

सीएम सलाहकार पर भी उठे सवाल

विधायकों ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नासिर सोगमी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन पर पार्टी नेतृत्व को गुमराह करने और संगठनात्मक

मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए गए हैं। विधायक उनके इस्तीफे, बिना शर्त माफी और पद से हटाने की मांग कर सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात और नेतृत्व की प्रतिक्रिया के बाद ही विधायक आगे की रणनीति तय करेंगे।

यदि सरकार अवैध घुसपैठ रोकने में विफल रहती है तो यह गंभीर चिंता का विषय

मौलाना मदनी ने अप्रवासी नागरिकों के अवैध प्रवेश को लेकर गृहमंत्री शाह पर बोला हमला

नई दिल्ली , एजेंसी। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हरियाणा के नूंह जिले में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अप्रवासी नागरिकों के अवैध प्रवेश और उन्हें देश से बाहर निकालने के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार अवैध घुसपैठ को रोकने में विफल रहती है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। मौलाना मदनी ने साफ किया कि भारत में किसी भी विदेशी नागरिक का अवैध रूप से प्रवेश स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानूनी तरीके से भारत आते हैं, उनके लिए देश में कानून मौजूद है, लेकिन जो अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं, उन्हें तुरंत देश से बाहर किया जाना चाहिए।

मदनी का मानना है कि अवैध रूप से देश में आने वाले लोगों को बाहर निकालने से भी ज्यादा जरूरी है कि उनके प्रवेश को ही रोका जाए। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि अगर सरकार विदेशी नागरिकों को देश में आने से रोकने में नाकाम रहती है और इसके लिए दूसरों पर आरोप लगाती है, तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर आप दूसरे देशों के नागरिकों को इस देश में आने से रोक नहीं सकते तो, आपसे बड़ा गद्दार इस मुल्क में कोई नहीं है। यह बयान अवैध अप्रवासन के मुद्दे पर सरकार की नीति और उसके कार्यान्वयन पर सीधा प्रहार था।

बता दें गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में संसद को घुसपैठ से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए थे, जिनमें बांग्लादेश से 7528, पाकिस्तान से 420, म्यांमार से 298, नेपाल और भूटान से संयुक्त रूप से 157 घुसपैठ के प्रयास दर्ज किए गए थे, जबकि चीन से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा के

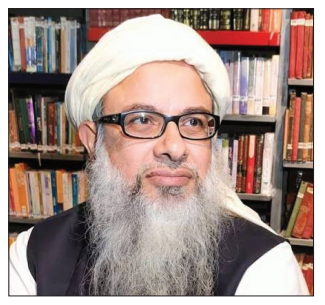

लिए अवैध घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण जरुरी है।

अगर मैच का अंपायर ही पक्षपाती हो, तो फिर खेलने का क्या मतलब?

पायलट ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी । दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पक्षपात किया है और भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता को खतरे में डाल दिया है। पायलट ने कहा कि आज चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस ईसीआई के खिलाफ जन महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है।

पायलट का मानना है कि एक कार्यशील लोकतंत्र में जनता का इन संस्थाओं पर भरोसा बना रहना और उसे मजबूत करना बहुत जरुरी है। पायलट ने मतदाता सूची से 13.3 करोड़ लोगों के नाम हटाए जाने पर भी अपनी गहरी चिंता जताई। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मैच का अंपायर ही पक्षपाती हो, तो फिर खेलने का क्या मतलब है? उन्होंने जनता के संस्थाओं में भरोसे पर जोर दिया। उनका कहना था कि जब स्वयं सिस्टम की निष्पक्षता पर ही शक हो, तो चुनावों में निष्पक्षता कैसे संभव है? पायलट ने कहा कि ज्ञानेश कुमार द्वारा की गई गलतियां अब पुख्ता सबूतों से साबित हो चुकी हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ जन महाभियोग प्रक्रिया जरुरी है।

उन्होंने सरकार पर संसद में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे इन मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाना जरुरत हो गया है। पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पहले की चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। उन्होंने उस नए कानून पर आपत्ति जताई जो सीईसी को पद छोड़ने के बाद भी जीवन भर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। पायलट ने तर्क दिया कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त देश के ऐसे इकलौते व्यक्ति होंगे, जिन्हें पद छोड़ने के बाद भी जीवन भर सुरक्षा मिलेगी, जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खुफिया एजेंसी के निदेशक या सेना प्रमुख को भी यह सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने इस कदम के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए इसे सरकार की मंशा पर चिंताजनक बताया।

पायलट ने बताया कि विपक्ष चुनावी संस्थाओं से जुड़े इन अहम मुद्दों पर लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं से पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से काम करने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें राजनीतिक विचारधारा और जुड़ावों से ऊपर उठना चाहिए। पायलट ने इन मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाने के विपक्ष के फैसला का बचाव करते हुए कहा कि संसद के ठीक से काम न करने और सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के उचित जवाब न मिलने के कारण यह जरुरी हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई पहले से ही कई स्तरों पर लड़ी जा रही है। उनका मानना है कि जनता का संस्थाओं पर भरोसा बना रहना चाहिए, लेकिन जब स्वयं व्यवस्था की निष्पक्षता पर ही प्रश्नचिह्न लगे तो यह विश्वास डगमगा जाता है।

दिल्ली में जूता फैक्ट्री में भीषण आग, दम घुटने से 4 की मौत, 2 गंभीर

नई दिल्ली, एजेंसी। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात जूते बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बेसमेंट से शुरू हुई इस आग की चपेट में आने और दम घुटने से कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। दमकल विभाग की करीब 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे ऊपरी मंजिलों में फैलने से रोका। दिल्ली अग्निशमन और पुलिस की टीमों ने फैक्ट्री के अंदर फंसे 6 लोगों को बेहोशी की हालत में निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेज-1 स्थित प्लॉट संख्या बी-293/294 में हुआ। यह जूता निर्माण और भंडारण की यूनिट थी। आग की शुरुआत बेसमेंट से हुई थी, जहां अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री, रबर और केमिकल रखे होने के कारण घना धुआं तेजी से फैल गया। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई कर लपटों को बेसमेंट तक ही सीमित रखा, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

कैदियों के भागने के मामले में सीएम विजय का एक्शन, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट निलंबित

17 कर्मचारियों को भी किया निलंबित, अब सभी जेलों में हथियारबंद गार्ड होंगे तैनात

चेन्नई, एजेंसी । तमिलनाडु के थेनी जिला जेल से हाल ही में 17 कैदियों के फरार होने के गंभीर मामले में सीएम विजय ने सख्त एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने थेनी जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एन रामलिंगम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सुरक्षा में हुई चूक के बाद यह फैसला लिया गया, जिसने राज्यभर की जेल सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे।

जानकारों के मुताबिक अगस्त 2024 से थेनी में तैनात डिप्टी जेल अधीक्षक एन रामलिंगम को जेल प्रशासन और सुरक्षा निगरानी में विफलता का दोषी पाया गया, जिसके कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है। उनके साथ कुल 17 अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद सरकार ने तमिलनाडु की सभी केंद्रीय और जिला जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का अहम फैसला लिया है। जेल और सुधार सेवा के पुलिस महानिदेशक संदीप राय राठौर ने इस जानकारी की पुष्टि की है। यह तैनाती सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का हिस्सा है।

पुलिस महानिदेशक संदीप राय राठौर ने बताया कि अब सभी जेलों के वॉचटावरों पर हथियारबंद जवान तैनात किए जाएंगे, जिन्हें भागने की कोशिश करने वाले किसी भी कैदी को देखते ही गोली मारने का निर्देश दिया जाएगा। यह एक अहम नीतिगत बदलाव है, क्योंकि अभी तक राज्य की ज्यादातर जेलों में वॉचटावरों पर तैनात गार्ड हथियार नहीं रखते थे। इसके साथ ही सभी जेलों में अलार्म सिस्टम ठीक से काम करें, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा ऑडिट पूरा होने और नई संचालन प्रक्रिया लागू होने के बाद अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

बता दें 26 अक्टूबर की रात को थेनी जेल से जेलकर्मियों को घायल कर 17 कैदी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 17 विशेष टीमें बनाकर इन सभी कैदियों को जल्द ही पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद सभी कैदियों को उच्च सुरक्षा वाली जेलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।